A Daily News Magazine

इंदौर

शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 174, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' व हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति में संतुलन जरूरी

जनरल मनोज नरवणे (रि)

रायसीना डायलॉग' की दसवीं कड़ी का आयोजन नई दिल्ली में 17-19 मार्च को किया गया। इसका, उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित इस डायलॉग ने बीते दस साल में अपना रुतबा बढ़ाया है और दुनियाभर के वरिष्ठ सत्ताधारियों और कूटनीतिज्ञों को आकर्षित कर रहा है। भू-राजनीति से लेकर जलवायु परिवर्तन तक तमाम वैश्विक मसलों पर चर्चा और बहस के इस मंच ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भारत की भूमिका को मजबूती दी है, जिसे कई विदेशी वक्ताओं ने भी स्वीकार किया है। इस बार का संवाद ट्रंप-2 शासन की घरेलू तथा विदेशी नीतियों के विश्वव्यापी परिणामों की आशंका की छाया से प्रभावित रहा, इनको लेकर चिंताएं बंद कमरों की चर्चाओं में ज्यादा खुलकर व्यक्त की गईं।

'अमेरिका फर्स्ट' वाले रुख ने विश्व-व्यवस्था में, जो कि यथास्थिति की आदी हो चुकी थी, उथल-पुथल कर दिया है। इसने पुराने गठबंधनों पर सवालिया निशान लगा दिया है, दोस्तों को दुश्मन बना दिया है और दुश्मनों की एक-दूसरे के करीब ला दिया है। इस तरह का विध्वंसक नेतृत्व स्थापित संस्थाओं और नौकरशाही ढांचों को चुनौती देता है और अक्सर बेहतर तथा कुशल परिणाम देता है। फिलहाल, शुरुआती घोषणाओं ने क्षेत्रों और समूहों को अपनी समस्याओं को और उनके लिए अपनी ज़िम्मेदारी को कबूलने पर मजबूर किया है। यह बात यूरोपीय संघ और उसके नाटो सदस्यों पर सबसे ज्यादा लागू होती है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह टिप्पणी याद कीजिए : 'यूरोप सोचता है कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं लेकिन दुनिया की जो समस्याएं हैं वह यूरोप की समस्याएं नहीं हैं।' इसी तरह, गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने और उसे पूरब का 'रिवेरा' बना देने की धमकी जैसे विध्वंसक प्रस्ताव का पश्चिम एशिया ने फौरन विरोध किया।

यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता करवाने और पुतिन को रियायतें तक दिलवाने की पेशकश करके अमेरिका ने युद्ध को अस्थायी तौर पर ही सही, रोकने की ज़रूरत को एक बार फिर दोहराया है। पिछले अमेरिकी शासन से इस तरह के रुख की कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह प्रधानमंत्री मोदी की इस भविष्यदर्शी टिप्पणी को प्रतिध्वनित करता है कि 'यह युद्ध का दौर नहीं है।' अमेरिका ने रूस की तरफ जो हाथ बढ़ाया है, उसने इस युद्ध के मामले में भारत के सिद्धांतवादी रुख को; उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका, रूस, चीन के साथ संबंधों संतुलन बरतने के उसके प्रयासों को सही साबित किया है। भारत ने अमेरिका के दबाव में अपने पुराने मित्र रूस से संबंध अगर तोड़ लिया होता, तो अब अमेरिका ने जो पलटी मारी है उसके चलते वह मुश्किल में फंस जाता।

अमेरिका ने बिना भेदभाव किए दुनिया के सभी देशों पर जिस तरह शुल्क (टैरिफ) थोपने का एकतरफा फैसला किया है, वह विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसकारी साबित हो सकता है। अभी इतनी जल्दी यह कहना मुश्किल है कि इन शुल्कों से अमेरिका या विश्व अर्थव्यवस्था को लाभ होगा या नहीं, लेकिन इसके जवाब में कुछ देशों ने रियायतों की पेशकश की, जिससे अमेरिका का रुख कुछ नरम हुआ है। कुछ देशों ने जैसे को तैसा जवाब है। बल्कि चीन ने आगे बढ़कर यह कहा है कि 'अमेरिका अगर युद्ध ही चाहता है, तो 'टैरिफ' युद्ध हो व्यापार युद्ध, या और किसी तरह का युद्ध, हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं।' चुनौती दे दी गई है, अब वक्त ही बताएगा कि व्यापार युद्ध असली युद्ध में तब्दील होता है या नहीं। फिलहाल तो इसने चीन और भारत को करीब ला दिया है, बावजूद इसके कि दोनों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से जारी है। तमाम देश जबकि व्यापारिक सहयोगी की तलाश में रहते हैं, यह विच्छेद अमेरिका को अंततः महंगा पड़ेगा।

समग्रता में देखें तो ये बदलाव भारत के लिए कुछ फायदेमंद हो सकते थे, लेकिन उनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि अमेरिका-चीन संबंधों में जब भी गिरावट आएगी, भारत खुद को दुनिया की सप्लाइ चेन में मैनुफैक्चरिंग के एक मजबूत केंद्र के तौर पर बीजिंग के विकल्प के रूप में पेश कर सकेगा। भारत को अपने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत भी है। रक्षा मामलों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ज़ोर देने और 'क्वाड' को बढ़ावा देने से भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा और यह एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के उभार का मुकाबला करने के लिए सहयोगियों की अमेरिकी तलाश के भी अनुकूल होगा।

इसका दूसरा पहलू यह है कि खासकर व्यापार समेत दूसरे मसलों पर ढुलमुल नीतियां भारत के लिए निरंतर बदलती वैश्विक आर्थिक गति से तालमेल बिठाने में दिक्कत पैदा करती हैं, खासकर बोझिल नौकरशाही प्रक्रियाओं के चलते। हमारी नीति लचीली होनी चाहिए ताकि जल्दी से अपनाई और लागू की जा सके और वह हमें आगे रख सके। इसके अलावा, प्रवासियों के मामले में खासकर एच-1बी वीज़ा के मामले में सख्त नीतियां भारतीय कामगारों, खासकर 'Tech' समुदाय के लिए काफी नुकसानदेह साबित होंगी। वह न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं, बल्कि भारत को पैसे भेजने के मामले में यूएई में बसे प्रवासी भारतीयों के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह, खास तौर से जलवायु परिवर्तन के मसले पर और दूसरे अन्य मसलों पर वैश्विक संगठनों और समझौतों से हटने का एकतरफा अमेरिकी फैसला भारत के कूटनीतिक कौशल की कड़ी परीक्षा लेगा।

इस गतिशील भू-राजनीतिक परिस्थिति का सामना करते हुए हमें आसन्न खतरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत जिन भू-राजनीतिक परिस्थितियों से घिरा है, उनके कारण उसे किसी समूह या गठबंधन से ऐसे वादे नहीं करने चाहिए, जिनके कारण दूसरे देशों से संबंध बनाने या किसी संकट में ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाने की उसकी क्षमता कमजोर पड़े। न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बल्कि चीन को परे रखने के लिए भी हमें 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति को और धारदार बनाना होगा। अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जगह हमें आर्थिक समझौतों, कूटनीतिक प्रयासों और अपने 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग करना चाहिए। आखिरकार, रोज़ाना की ज़िंदगी के सभी पहलुओं, खासकर रक्षा और राष्ट्रीय स्तर के ग्रिडों के मामलों में तकनीकी पर बढ़ती निर्भरता के मद्देनज़र भारत को साइबर सिक्योरिटी को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का अहम तत्व बनाना होगा ताकि हम इतने सक्षम हों कि सर्वव्यापी साइबर खतरों से खुद को बचा सकें।

अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे 'सुप्रीम' जज

- एससी का बड़ा फैसला, जानकारी भी वेबसाइट पर होगी अपलोड
- दिल्ली एचसी जज वर्मा के घर कैश मिलने के बाद हुआ निर्णय

नई दिल्ली (एजेंसी)। ज्यूडीशियरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डीटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि, वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि, इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा

के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लगी थी। फायर सर्विस टीम को वहां अधजले नोट मिले थे। 1997 का प्रस्तावः 1997 में, तत्कालीन सीजेआई जे एस वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि, यह घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी। 2009 का न्यायाधीश संपत्ति विधेयकः 2009 में, न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने कहा गया था। हालांकि, इसमें यह प्रावधान था कि घोषणाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। इस प्रावधान के कारण विधेयक को विरोध का सामना करना पड़ा और इसे स्थगित कर दिया गया। 2009 में सूचना के अधिकार के तहत कुछ जजों ने संपत्ति की जानकारी दी थी।

सुप्रभात

तुम नहीं मिलती तो भी
मैं
नदी तक जाता
छूता उसके हृदय को
गाता
बचपन का कोई पुराना अधूरा गीत
तुम नहीं मिलती तो भी

तुम नहीं मिलती तो भी
पहाड़ के साथ घंटों बतियाता
वृक्षों का हाथ पकड़ ऊपर की ओर
उठना सीखता
बीस और इक्कीस की उमर की
कोई न भूलने वाली घटना को
स्मरण करता
कपड़े के जूते में सिहर कर पैर रखता
तुम नहीं मिलती तो भी

तुम नहीं मिलती तो भी
जितना भी मेरे पास पिता था
उतना भर बच्चा जनता ही
रचता ज़रूर एक आदमी का संसार
कुछ अदद काँटों के बीच एक बेहद
नाज़ुक कोई फूल भी खिलाता ही

बस एक बात अलग होती
एक दरवाज़ा होता कभी नहीं बंद होने वाला
एक क़ैद अँधेरे से लड़ती चिड़िया होती
तुम नहीं होती तो भी
मैं नदी तक जाता ही।

– अक्षय उपाध्याय

गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य

- राज्यसभा में रिजिजू बोले-वक्फ में गैर-मुस्लिमों का दखल नहीं होगा
- कांग्रेस ने कहा-यह मुस्लिमों के खिलाफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। रिजिजू ने कहा- संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। रिजिजू ने कहा- दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। जब इतनी प्रॉपर्टी देश में है और करोड़ों गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, ऐसे में यह किसी काम की नहीं।

हमने ट्रेन, प्लेन में नमाज पढ़ ली तो क्या वो हमारा हो गया

हुसैन ने कहा– बार–बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकता है। क्या भारत में कोई कानून नहीं है। अगर हमने ट्रेन, प्लेन में नमाज पढ़ ली तो क्या ट्रेन–प्लेन हमारा हो गया।

कांग्रेस बोली-

पोलराइजेशन के लिए बिल लाया गया– कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा– इनको 2024 में क्यों याद आया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी नहीं मिली। इसलिए ये पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। सभी जानते हैं कि देश में कौन ध्रुवीकरण करता है। ये बिल मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन पर है कितने इसके अगेंस्ट हैं।

ये बिल परेशान करने के लिए लाया गया है– खरगे

राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर बोलते हुए सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, ये बिल परेशान करने के लिए लाया गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

वक्फ बिल के विरोध में JDU के 2 लीडर्स ने पार्टी छोड़ी

बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नीतिश के नेता ने पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन करने पर पार्टी छोड़ दी। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उनके अलावा मोहम्मद नवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है।

बीजेडी बोली– कोई व्हिप जारी नहीं किया, सांसद खुद से फैसला लें

बीजू जनता दल ने वक्फ बिल पर कहा है कि पार्टी ने अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं किया है। सांसद अपनी अंतरआत्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें।

सीएम मोहन यादव का ऐलान

प्रदेश में सड़क मार्ग से जुड़ेंगी 50 हजार बसाहटें

भोपाल (नप्र)। प्रदेश सरकार अगले तीन साल में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर कार्य-योजना बनाई जाए। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में पीएम ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल, सीएस अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

एआई का करें उपयोग– सीएम ने कहा, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्त, उन्नयन के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। सड़कों के रखरखाव, निरीक्षण में ऐप, जियो टैगिंग और एआइ का उपयोग कर और प्रभावी बनाया जाए।

बैठक में बताया गया कि 89 हजार बसाहटों में से 50,658 बसाहटें सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। ग्राम सड़क योजना-4 के तहत बनने वाली 11,544 बसाहटों के लिए सर्वे कर लिया गया है। शेष 26,798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है।

गृह भाड़ा भत्ता से संतुष्ट नहीं कर्मचारी, कहा– इतने में तो झुग्गी भी किराए पर नहीं मिलेगी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों का परिवहन भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आगे भी सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन से कर्मचारियों का ध्यान रखेगी। उधर कर्मचारी जगत ने 13 साल बाद बढ़ाए गए भत्तों को लेकर कहा है कि यह केंद्र सरकार से काफी कम है। इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाता तो लाभ मिलता। अभी जो भत्ता बढ़ाया गया है उससे तो किराए में झुग्गी भी नहीं मिल पाएगी।

जनहितैषी कामों का मूल आधार हैं अधिकारी–कर्मचारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि हम लगातार जनहितैषी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन जनहितैषी कामों के मूल आधार हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं। इसलिए हमने 15 साल से रुके भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसके बाद सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा।

पीएम मोदी थाईलैंड पहुंचे, भारतीय समुदाय से मिले

- थाई रामायण का मंचन देखा, पीएम शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की

नई दिल्ली/बैंकॉक (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। राजधानी बैंकॉक पहुंचकर उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यहां रामायण को रामाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। यात्रा के दूसरे दिन यानी कल पीएम मोदी बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के बाद वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूनुस के मुख्य सलाहकार खलीलुर रहमान ने बुधवार को इसकी संभावना जताई है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। मोदी शुक्रवार को थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न और रानी सुथिदा से भी मुलाकात करेंगे। 2024 में थाक्सिन शिनवात्रा की बेटी पाइतोंग्तार्न

शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनीं। अक्टूबर 2024 में वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। मोदी इससे पहले 2016 में थाईलैंड के नौवें राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को श्रद्धांजलि देने गए थे। इसके बाद वे 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड गए थे। उनकी यह तीसरी, लेकिन पहली आधिकारिक यात्रा है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच बातचीत का एजेंडा राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, रक्षा, संपर्क और सुरक्षा होगा।

भारत–थाईलैंड संबंध 2 हजार साल से भी ज्यादा पुराना– भारत और थाईलैंड के संबंध दो हजार साल से भी अधिक पुराने हैं। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। थाईलैंड में रामायण को 'रामकियेन' के रूप में जाना जाता है, जो वहां की संस्कृति का हिस्सा है। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया। थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 'स्वर्णभूमि' (सोने की भूमि) कहा गया है। थाईलैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी पुराना और मजबूत रहा है। 1947 में दोनों देशों ने औपचारिक संबंध की शुरुआत की।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22°c
न्यूनतम 16°c

2

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सप्तम मां कालरात्रि

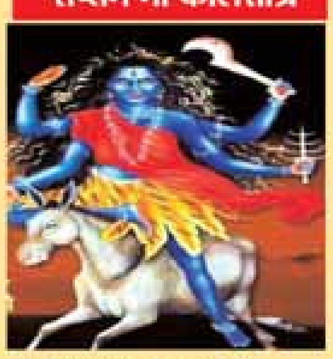

मां के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह मां का अति भयावह व उग्र रूप है। सम्पूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं। किन्तु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है।

कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन

● भारत अंतरिक्ष में एक बार फिर से रचेगा नया इतिहास

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के साथ चल रहे नए मिशन का हिस्सा होंगे। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। यह मिशन एx-4 का हिस्सा होगा। इस मिशन की लॉन्चिंग तारीख सामने आ गई है। इसे नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट हैं।

वह भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए एस्ट्रोनॉट्स में शामिल हैं। एx-4 मिशन में वह स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इस मिशन का नेतृत्व पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन करेंगी। उनके साथ पोलैंड के सावोस उज़्नान्स्की-

विस्नेवस्की और हंगरी के टिबोर कापू मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल होंगे। यह 14 दिन का मिशन है, जिसमें विज्ञान से जुड़े प्रयोग, शैक्षिक कार्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियां की जाएंगी। शुभांशु शुक्ला इस दौरान भारत की संस्कृति को भी अंतरिक्ष में प्रदर्शित करेंगे। वह अलग-अलग भारतीय राज्यों से जुड़ी कलाकृतियां लेकर जाएंगे और अंतरिक्ष में योग करने का भी प्रयास करेंगे। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती ताकत और वैश्विक सहयोग को दर्शाता है। इस मिशन के जरिए नासा और इसरो के बीच सहयोग मजबूत होगा, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष की खोज और अंतरिक्ष यात्राओं के नए रास्ते खुलेंगे। शुभांशु शुक्ला ने कहा,यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों और सपनों की उड़ान है।

उत्तर भारत में गर्मी मचाने वाली है तांडव

पांच डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ने वाला है। अगले सात दिनों में गर्मी का तांडव दिखने वाला है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। दो से छह अप्रैल के बीच दक्षिण भारत में भारी बारिश होगी। हीटवेव की बात करें तो सौराष्ट्र और

कच्छ में अगले सात दिनों तक इसका कहर देखने को मिलेगा। वहीं, पश्चिमी राजस्थान में सात और आठ अप्रैल को हीटवेव चलने वाली है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु में तेज हवाएं चलीं। वहीं, तमिलनाडु में भारी बरसात हुई। इसके अलावा, मध्य महाराष्ट्र में ओले गिरे। सौराष्ट्र और कच्छ में हीटवेव रिकॉर्ड की गई। दक्षिण भारत की बात करें तो 2-6 अप्रैल के बीच आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अलर्ट है। इसके अलावा, मध्य भारत, झारखंड, ओडिशा में दो से चार अप्रैल के बीच बारिश होगी।

देवास में नेमावर घाट पर एक साथ जलीं 18 लोगों की चिताएं

● गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट में गई थी 20 की जान, दो शवों की पहचान बाकी

नेमावर (नप्र)। गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 से 8 साल तक के बच्चे भी हैं। ये सभी मध्यप्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। देवास के नेमावर घाट पर गुरुवार को 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाकी दो शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया गया। इनमें से एक की पहचान लक्ष्मीबेन अनिल भाई नायक, उम्र-50 साल, हंडिया, जिला हरदा के रूप में हुई है। एक शव की पहचान बाकी है। ये शव अभी गुजरात में ही हैं।

बनासकांठा के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फट गया था। धमाका इतना भीषण था कि कई मजदूरों के शरीर के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं।

हादसे में हरदा के हंडिया के 8 और देवास के संदलपुर के 9 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, खातेगांव के ठेकेदार की भी जान चली गई थी। 8 मजदूरों का इलाज चल रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर है।

प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार- ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 18 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। नर्मदा घाट (नेमावर) पर शवों को मुखाग्नि दी गई। देवास के 9 मजदूरों के शव पहले उनके पैतृक गांव संदलपुर पहुंचे। ठेकेदार का शव खातेगांव पहुंचा। अंतिम दर्शन के बाद सभी शवों को नेमावर घाट लाया गया। वहीं, हरदा के हंडिया के लोगों के शव गुजरात से सीधे नेमावर घाट लाए गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों की आंखें नम हैं।

एम्बुलेंस के जरिए एमपी लाए गए सभी शव

शवों को लेने पुलिस-प्रशासन टीम के साथ मंत्री नागर सिंह गुजरात गए थे। बुधवार सुबह देवास के 10 मजदूरों के शव उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किए गए। बाकी शव पोस्टमॉर्टम के बाद भिजवाए गए।

खातेगांव और संदलपुर के लिए गुजरात से आ रहीं सभी एम्बुलेंस और उनके साथ चल रहे गुजरात प्रशासन की ओर से अश्विन सिंह राठौर, नायब तहसीलदार और उनकी टीम शाम 6 बजे दाहोद से निकलने की तैयारी में थी। इसी बीच एक एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद एम्बुलेंस बदली गई और शवों को रवाना किया गया।

देवास जिले में एक साथ इतने शवों को आइस बॉक्स में रखने की सुविधा नहीं है। इसलिए सभी शवों को इंदौर एमवाय अस्पताल की मॉर्चुरी में रखा गया। गुरुवार सुबह इंदौर से शवों को संदलपुर ले जाया। परिजन ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शवों को नेमावर घाट भेजा गया।वहीं, हरदा के हंडिया के परिवार के शवों को इंदौर से सीधे नेमावर घाट लाया गया। परिजन ने एम्बुलेंस में ही आखिरी शवों को देखा।

अदालत का सम्मान, फैसला स्वीकार नहीं

26 हजार भर्ती खारिज होने पर ममता बनर्जी के सख्त तेवर

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में करीब 26 हजार टीचरों एवं अन्य स्टैफ की भर्ती को अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है तो वहीं

सीपीएम का कहना है कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता ने कहा कि मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए।

स्पैम कॉल्स से परेशान करने वालों पर मोदी सरकार का ऐक्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। फालतू कॉल्स से परेशान करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। संचार मंत्रालय यानी डीओटी ने अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत स्पैम कॉल्स से जुड़े 1.75 लाख अनऑथराइज्ड नंबरों को डिस्कनेक्ट किया गया है। संचार मंत्रालय ने कंपनियों से दूरसंचार नियमों का पालन करने की अपील की है। बताया गया है कि 0731, 079, 080 से

शुरू होने वाले नंबरों पर कार्रवाई की गई है। इन नंबरों से बड़ी संख्या में लोगों को स्पैम कॉल्स आ रही थीं। इसके बाद सरकार की ओर से तमाम डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग नंबरों को डिस्कनेक्ट किया गया। जिन नंबरों पर कार्रवाई की गई है, वो अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। याद रहे कि लोग आए दिन कॉल्स से परेशान होते हैं। इनसे सेवाओं का प्रचार किया जाता है या किसी तरह की स्कीम होती है।

12 अवैध फार्महाउस पर चलाया गया बुलडोजर

फरीदाबाद (एजेंसी)। अवैध रूप से बनाए फार्महाउस और कॉलोनियों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम ने बुधवार को मौजाबाद और किडावली में बने 12 अवैध फार्म हाउसों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। बता दें कि यमुना किनारे बसे इन गांवों की खेती योग्य जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण कर दिया था। इसकी सूचना मिलते ही बुधवार को डीटीपी एन्फोर्समेंट की टीम मौके पर पहुंची और 12 फार्महाउसों को तोड़ दिया। इसके अलावा 50 बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया गया। डीटीपी

एन्फोर्समेंट राहुल सिंगला ने बताया कि इस तरह से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं बड़खल चौक पर भी कार्रवाई हुई।

बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा हमारी है

बैंकॉक (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिमस्टेक में अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और वह आर्थिक और भू-राजनीतिक गतिविधियों से अवगत है। उन्होंने कहा कि भारत का

मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है न कि चुनिंदा विषयों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है।

उनका यह बयान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने चीन के दौरे पर कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्य स्थलबद्ध (लैंड लॉक्ड) हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी और सटे हिन्द महासागर का वह अकेला संरक्षक है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का नवीनतम बयान कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा भारत की है यूनुस को तंज है।

महाराष्ट्र में अब शिंदे के पास जाएगी हर फाइल

● अजित पवार से ज्यादा हुई पावर,सारी शिकायतें दूर

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार में बीते कई महीनों से चली आ रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो वह होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन वह भी नहीं मिला तो कुछ मंत्रालय लेकर डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद भी उनकी नाराजगी बनी ही रही। कभी प्रभारी मंत्रियों को लेकर तो कभी मंत्रालयों के फैसलों को लेकर वह खफा दिखते थे। एक मलाल यह भी रहा कि अजित पवार को उनसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के कामकाज

की कोई भी फाइल उनसे होकर ही सीएम देवेंद्र फडणवीस तक जाएगी। इस निर्णय से शिंदे खुश हो गए हैं।

ट्रंप के 26 फीसदी वाले झटके से भी खुश मोदी सरकार

● चीन को मात देने की उम्मीद, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित 26 फीसदी जवाबी टैरिफ को लेकर मोदी सरकार ने संतुलित और सुनियोजित रुख अपनाने का फैसला किया है। ट्रंप सरकार के फैसले से भारत के श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले भारत को बढ़त मिलेगी। सरकार इस प्रभाव का आकलन करने में जुटी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में वाणिज्य मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय बैठक चल रही है, जिसके बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, भारत को चीन पर 54-79

फीसदी का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। इसी तरह, वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले भी भारतीय कपड़ा निर्यात को मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि चीन को पीछे छोड़ने की उम्मीद के साथ मोदी सरकार इसे न सिर्फ एक चुनौती के रूप में, बल्कि एक अवसर के तौर पर भी देख रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप सरकार के टैरिफ वाले फैसले से कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों को अप्रत्याशित लाभ होगा। हालांकि, भारत इस फैसले को लेकर कोई जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देगा। भारत अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाएगा। प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, झींगा निर्यात और स्टील उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जबकि फार्मा सेक्टर मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा नुकसान नहीं झेलेगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा,भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और पेशेवर होगी। कुछ देशों की तरह हम अमेरिकी आयात पर जवाबी कार्रवाई की धमकी नहीं देंगे।

जानलेवा होती जा रही हैं भारत की पटाखा फैक्ट्रियां

● इस साल अब तक 40 लोगों ने गंवाई अपनी जिंदगी ● गुजरात और पश्चिम बंगाल में हुए यह दर्दनाक हादसे

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल भारत में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है। मंगलवार एक अप्रैल को गुजरात की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.रॉयटर्स के मुताबिक, धमाका इतना भयानक था कि कई मृतकों के शरीर के अंग 200-300 मीटर दूर एक खेत में बिखरे हुए मिले। ज्यादातर मृतक मध्यप्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे।

एक हादसा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भी हुआ। यहां एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग गई जिसकी चपेट में आने से एक परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, इस साल पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले, फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग घायल हो गए थे। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित सिवकासी को भारत में पटाखा निर्माण का केंद्र माना जाता है। विरुधुनगर में हजार से ज्यादा पटाखा फैक्ट्रियां हैं।

हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना- एक रिपोर्ट बताती है कि विरुधुनगर की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पटाखा निर्माण से जुड़ी हुई है। यहां की सूखी और गर्म जलवायु के चलते यहां पटाखा बनाना आसान होता है। यहां के पटाखा उद्योग ने साल 2020-21 में 112 करोड़ रुपए टैक्स में दिए थे। पटाखा फैक्ट्रियों में होने वाले हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है। पिछले साल मध्य प्रदेश की जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उसमें अनुमति से ज्यादा पटाखे बन रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री संचालकों के पास केवल 15 किलो विस्फोटक का लाइसेंस था लेकिन फैक्ट्री में इससे कई गुना ज्यादा बारूद रखा हुआ था। इस फैक्ट्री में पहले भी हादसे हो चुके थे लेकिन फिर भी पटाखे बनाने का काम नहीं रोका गया था। साल 2021 में विरुधुनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक कमेटी बनाई थी।

महापौर ने नगर निगम का 8 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया

इंदौर के हर घर का अब डिजिटल पता

468 करोड़ से सड़कें, 200 करोड़ से बनेगा सीएनजी प्लांट

जनता पर नहीं लगेगा नया टैक्स

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर नगर निगम का 8 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट गुरुवार को नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह में पेश किया गया। इस साल नया टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया। नगर निगम का नया पोर्टल अब 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई। इसके लिए अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। गुरुवार को दो घंटे बीस मिनट में बजट खत्म हो गया। सभापति ने बैठक को स्थगित कर दिया। अब शुक्रवार 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी। बजट में शामिल होने से पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी जूही भार्गव ने परंपरागत तरीके से महापौर को दही-शक्कर खिलाया।

बजट भाषण से पहले हुआ हंगामा

बजट सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सदन में निगम में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महापौर जवाब दें कि अब तक क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट तक चले हंगामे के बाद महापौर ने बजट भाषण शुरू किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे मौजूद हैं। मंत्री सिलावट ने महापौर को बजट से पहले माला पहनाई। इस बजट में सबसे ज्यादा 2 हजार करोड़ रुपए जनकार्य विभाग के लिए रखे गए हैं।

मनोरंजन कर पर पिछले साल से सख्ती बढ़ाई

मनोरंजन कर पर पिछले साल से सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे इस साल 5 से 10 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। इंदौर में बजट से पहले निगम सदन में देश के विभिन्न जगहों पर हुए दुखद हादसों में व इंदौर के समाजसेवियों व राजनेताओं के यहां हुए परिजनों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रदेश में किसी निगम ने आज तक इतना टैक्स वसूला नहीं है- इंदौर नगर निगम ने जो 1 हजार करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है यह एक रिकार्ड है। प्रदेश में किसी निगम ने आज तक इतना टैक्स वसूला नहीं है। बजट शुरू होने के दो घंटे बाद दोपहर 1 बजे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम पहुंचे। उन्हें देखते ही महापौर ने अपना भाषण रोक दिया। और फिर मंत्री का स्वागत किया।

विपक्ष सही और गलत दोनों के विरोध के लिए, उन्हें जनता ने विरोध करने ही बैठाया है : मंत्री विजयवर्गीय

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा प्रतिपक्ष को विरोध करना चाहिए सही बात पर भी और गलत बात पर भी। उन्हें जनता ने विरोध करने बैठाया है। कभी पैसों की कमी नहीं आने देंगी ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुझ पर इंदौर की जनता का ऋण है, मुझे कई मौके मिले हैं, जब मुझे यह चुकाने का अवसर मिला। महापौर जी आप काम कीजिए, बहुत काम कीजिए। काम करने का बहुत अच्छा अवसर है। मुझे अपने जीवनकाल में सबसे ज्यादा काम करने का मजा मेरे महापौर काल में आया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में सभी निगम और पालिका की हालत यह है कि भोपाल से जब पैसा भेजा जाता है तभी वेतन बंटता है। अब जो भी भोपाल या दिल्ली से पैसा आएगा वह अब इंदौर के विकास के लिए काम आएगा। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मैं यहां मंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं। शहर के नागरिक और विधायक की हैसियत से आया हूं। सभापति और निगम को धन्यवाद देने आया हूं कि नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है।

जू में बनेगा फिश एक्वेरियम, जिराफ भी आएगा

हमारा प्राणी संग्राहलय हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है जिसे देखने के लिए पूरे प्रदेश से पर्यटक आते हैं। इस संग्राहलय में मप्र का सबसे सुंदर फिश एक्वेरियम के लिए एमआईसी ने स्वीकृति दे दी है। आने वाले साल में मप्र का सबसे सुंदर फिश एक्वेरियम हमारे जू की शोभा बढ़ाएगा। चिड़ियाघर ने अपनी पहचान ब्रिडिंग सेंटर के रूप में बनाई है। इसके साथ ही राजस्व और मनोरंजन को बढ़ाने के लिए काफी काम किए जा रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज के तहत इंडियन गौर को लाया जाएगा। हमारे प्राणी संग्रहालय में निकट भविष्य में जिराफ आने की भी संभावना है।

कचरा कलेक्शन के लिए खरीदेंगे सौ इलेक्ट्रिक वाहन- महापौर ने कहा कि इस साल हम 28 चौराहों के लेफ्ट टर्न का चौड़ीकरण करेंगे। पार्किंग की सुविधा को देखते हुए इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा।

15 करोड़ रुपए की लागत से हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे

बीआरटीएस को हटाने का निर्णय सीएम ने लिया। जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

बजट में ये भी शामिल किया

मास्टर प्लान की सड़कों का रिकॉर्ड इंदौर के इतिहास में 450 करोड़ की लागत से एक साथ 23 मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह भी अपने आप इंदौर के लिए एक बड़ा रिकार्ड है। इन सड़कों के साथ ही हम 10 मास्टर प्लान की सड़क ओर बनाने का हम इस बजट में घोषणा कर रहे है।

ऐप पर कचरा कलेक्शन: इंदौर डिजिटल ही कचरा प्रबंधन में आगे बढ़ेगा। एप के माध्यम से डिजिटल कचरा कलेक्ट करने वाला शहर बनेगा।

बायो सीएनजी प्लांट: देवगुराड़िया स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की क्षमता 800 टन तक बढ़ाई जाएगी।

सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन एरिया: पोलोग्राउंड की जो जमीन निगम को मिलने वाली है। वहां सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन एरिया बनाया जाएगा। वहीं शहर के 6 क्षेत्रों में 500 किमी की ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी।

इंदौर के हर घर को मिलेगा डिजिटल पता

महापौर ने कहा कि इंदौर का अपना डिजिटल पता भी हम शुरू करेंगे। इंदौर शहर के हर घर को एक डिजिटल पता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वार्ड क्रमांक 82 में अप्रैल माह में ही शुरू किया जाएगा।महपौर ने आगे कहा कि जब हमने शहर को सोलर सिटी बनाने का प्रण लिया था। आज हमारा यह प्रण मय प्रमाण के साथ सफल हुआ है।महापौर ने कहा कि सदन को बताना चाहता हूं की जलूद में 16 मेगावाट के पार्क के साथ इंदौर की जनता ने 25 हजार से ज्यादा घर की छतों पर सोलर रूफ टॉप लगे। फरवरी के अंत तक 800 मेगावाट बिजली की खपत इंदौर शहर करता है उससे में से 100 मेगावाट बिजली की ऊर्जा इंदौर खुद पैदा कर रहा है। गुजरात के बाद देश में कोई शहर है तो वह इंदौर है जिसने सोलर ऊर्जा 100 मेगावाट पर ले जाने का काम किया है।

कांग्रेस के शासन में काम होते ही नहीं थे, तो गलती भी नहीं होती थी, हंगामा

महापौर ने कहा कि कांग्रेस के विद्वान सदस्यों ने हर बैठक में हमारे विकास के कार्यों में गलती बताई। मैं विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रयासों को समझा। मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई क्योंकि तब काम ही नहीं होता था, तो गलती होने का प्रश्न हीं नहीं खड़ा होता था।महापौर ने आगे कहा महपौर ने आगे कहा कि जब हम इंदौर छोड़कर किसी और शहर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले याद आती है इंदौर की स्वच्छता और हमारी जनभागीदारी। हमारा इंदौर अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है जो स्वच्छता और नवाचार का रोल मॉडल बना है।

निगम पोर्टल – ये 2050 में उस समय की टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा

महापौर ने कहा कि डिजिटल पोर्टल का असंभव काम हमारे एमआईसी के साथियों के प्रयासों से यह संभव हो रहा है। मैं यह मानता हूं की 1 अप्रैल से हमें यह पोर्टल स्वीकार करना था। लेकिन अब वह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इसकी एजेंसी फाइनल हो गई है उसका टेंडर हो चुका है। 2050 में कोई पार्षद या अधिकारी उपयोग करते हुए यह ना कहें कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वह अब पुरानी हो गई इसलिए पूरा नया सिस्टम लाना पड़ेगा।हमनें एर्नेस्ट एंड यंग जैसी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी को टेंडर देने का काम किया है। जो आज से आने वाले 50 साल की तकनीक पर यह पोर्टल बना रही है। इस पोर्टल के लिए जो दो माह की देरी हुई है इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

चैत्र नवरात्रि -बिजासन माता

संतान की कामना लेकर आते हैं श्रद्धालु, बीज रूप में विराजमान हैं मां के नौ स्वरूप

इंदौर (एजेंसी)। चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन था। इंदौर के प्राचीनतम और प्रसिद्ध देवी मंदिरों में से एक बिजासन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में देवी नौ स्वरूप बीज रूप में विराजमान हैं। माता मंदिर का इतिहास एक हजार साल पुराना माना जाता है। पहले माता चबूतरे पर विराजमान थीं। इंदौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने 1760 में मंदिर का निर्माण कराया था।

तंत्र–मंत्र और सिद्धि के लिए प्रसिद्ध

मंदिर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर रेलवे स्टेशन से करीब 10 किमी दूर एयरपोर्ट के पास छोटी पहाड़ी पर स्थित है। वन क्षेत्र में स्थित इस मंदिर के आसपास काले हिरण पाए जाते थे। मंदिर के पास एक तालाब भी है, जो कभी नहीं सूखता, चाहे जितनी भी गर्मी हो। मंदिर के आसपास 12 अन्य छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जहां भक्त अलग-अलग देवी स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं।

संतान की कामना लेकर आते हैं भक्त

मंदिर के मुख्य सेवक सतीश गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में नौ देवी स्वरूप पिंडी (बीज) रूप में पूजी जाती हैं। बिजासन माता को सौभाग्य और संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है। इसके कारण विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े इस मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मन्नत का धागा भी बांधते हैं और बाद में उसे खोलने भी आते हैं। कई श्रद्धालु दंडवत होकर माता के दरबार तक पहुंचते हैं।

इंदौर के महाराजा ने मांगी थी मन्नत

गोस्वामी ने बताया कि इंदौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने संतान के लिए इस मंदिर में मन्नत मांगी थी। संतान प्राप्त होने के बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। शहर की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। बिजासन माता को विजयी की देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि आल्हा-ऊदल जब इस रास्ते युद्ध के लिए जाते थे, तो यहां पड़ाव डालते थे और माता की पूजा भी करते थे।संतान के लिए दंपती मन्नत मांगने आते हैं और पूरी होने के बाद माता के दरबार में पहुंचते हैं।

नवरात्रि में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त

वैसे तो बारह महीने मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में मंदिर में मेले का आयोजन होता है। यहां न केवल इंदौर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और आस-पास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के आसपास 12 अन्य छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जहां भक्त अलग-अलग देवी स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं।

दंपत्ति ने किया सुसाइड

पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाने की आशंका, भाईयों के बीच दुकान को लेकर था विवाद

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के छत्रीपुरा में रहने वाले एक दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया। बुधवार को दोनों के शव घर के अंदर लटके हुए मिले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव अस्पताल भेजे गए हैं। छत्रीपुरा पुलिस के मुताबिक घटना सेठी नगर की है। यहां रहने वाले गब्बर (45) पुत्र मांगीलाल यादव और उसकी सपना यादव ने दोपहर में अपने घर फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार गब्बर फर्नीचर कारीगर है। वहीं सपना हाउस वाइफ है। दोनों की शादी को 22 साल हो गए हैं। उनके दो बेटी और एक बेटा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिवार के लोगों के मुताबिक गब्बर के तीन भाई और हैं। जिसमें संतोष और राजू मृतक से बड़े हैं, वही सबसे छोटा भाई दिनेश है। गब्बर और दो भाई सेठी नगर में अलग-अलग घरों में रहते हैं। वहीं दिनेश अपने परिवार के साथ मूसाखेड़ी में रहता है। उनके पिता की लॉक डाउन में मौत हो चुकी है। दोस्तों ने बताया कि गब्बर के परिवार की एक दुकान बालदा कॉलोनी मेनरोड पर थी। जिसमें चारों भाईयों का हिस्सा था। काफी समय से दुकान बंद है। इसके बाद से गब्बर अपने भांजे की दुकान पर फर्नीचर का काम कर रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि उसे किराना दुकान पर खड़ा देखा था। करीब दो घंटे बाद उसकी और पत्नी की मौत की जानकारी मिली। सुसाइड के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।

रायसेन से वालमार्ट राऊ भेजी 16 लाख की सिगरेट गायब

वेयर हाउस कर्मचारी की शिकायत पर ट्रक चालक और हेल्पर के खिलाफ मामला दर्ज

इंदौर (एजेंसी)। रायसेन जिले के मंडीदीप वेयर हाउस से बेस्ट प्राइज (वालमार्ट) राऊ इंदौर का माल लेकर निकले ट्रक से 16 लाख की सिगरेट रास्ते में गायब हो गई। मेगा सिटी आनंद वेयर हाउस कैरियर आईटीसी लिमिटेड के कर्ताधर्ता मुडियाखेड़ा निवासी अंकित पिता नरेश तिवारी की शिकायत पर राऊ पुलिस ने सागर निवासी ट्रक चालक बिजवां और हेल्पर चिंटू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अंकित ने दोनों पर हेरीफेरी का आरोप लगाया है। अंकित ने बताया कि वेयर हाउस से 4 ट्रक में लोड कर सिगरेट और अन्य माल इन्वाइस, बिल्टी के साथ भेजा गया है पर वालमार्ट इंदौर प्रबंधन सिगरेट कम निकलना बता रहा है। वे बताते हैं कि वालमार्ट राऊ को सिगरेट, बिस्किट, आटा, नूडल, बिंगों, साबुन और अन्य मटेरियल हमेशा भेजा जाता है पर कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्वाइस और बिल्टी के मुताबिक पूरा माल भेजा गया था।

सड़क हादसे में घायल नाबालिग की मौत

8 दिन से थी कोमा में ; तीन सहेलियां हुई थी हादसे का शिकार, दो घायल

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के पास खुड़ैल में आठ दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल 16 वर्षीय आशा राठौर की बुधवार देर रात एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। आशा अपनी सहेलियों प्रियंका और शिवानी के साथ स्कूटी से पानी पुरी खाने गई थी, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों सड़क पर बेसुध पड़ी मिलीं। इलाज के लिए उन्हें पहले ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, फिर आशा को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और हादसे के बाद से वह होश में नहीं आई।

परिवार के अनुसार, प्रियंका और शिवानी का इलाज अलग-अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। आशा एक निजी कंपनी में काम

करती थी और उसके पिता व भाई भी निजी कंपनियों में ही नौकरी करते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत- बाणगंगा इलाके में बुधवार शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा नमकीन कलस्टर के पास हुआ, जहां 30 वर्षीय खेमा राय गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा मिला। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई।

साम्प्रदायिक आधार पर ट्रांसफर से राज्य मशीनरी विफल होगी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर हाईकोर्ट में बुधवार को धार्मिक भेदभाव के आधार पर ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि यदि इस तरह के निराधार आरोपों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार किया जाता है तो इससे प्रशासनिक आदेशों के क्रियान्वयन में गंभीर उल्लंघन होगा।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा, इस न्यायालय का मानना है कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो कल को मुस्लिम समुदाय का कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों, जो गैर-मुस्लिम समुदाय से हैं, के स्थानांतरण का आदेश पारित करता है तो वह भी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह की ऐसी आलोचना के अधीन हो सकता है, जिससे राज्य मशीनरी पूरी तरह विफल हो सकती है। परिणामस्वरूप अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इस प्रकार, इस तरह की प्रथा को केवल दहलीज पर ही हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने ट्रांसफर को राजनीति व धार्मिक आधारित बताया- रतलाम के याचिकाकर्ता नसीम उद्दीन सहित, रतलाम के ही प्रभारी सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पद पर रतलाम से छिंदवाड़ा ट्रांसफर

कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वे मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता के कहने पर ट्रांसफर किया गया। नसीम उद्दीन ने तर्क दिया कि उनका स्थानांतरण राजनीति से प्रेरित था। राज्य सरकार उन्हें रतलाम से किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करके धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने बोला– धर्म के आधार पर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश

राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए अपने जवाब में बताया कि याचिकाकर्ता ने धर्म का अनुचित लाभ उठाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से याचिका दायर की और ट्रांसफर के सामान्य आदेश को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। यह भी बताया कि यदि एक ही स्थान से एक समुदाय के चार व्यक्तियों को ट्रांसफर किया गया तो इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया ट्रांसफर नहीं माना जा सकता।

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,याचिकाकर्ता का 9 से 10 वर्षों से ट्रांसफर ही नहीं किया गया। जबकि स्थानांतरण नीति के खंड 16 और 17 के तहत प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी को तीन वर्ष पूरे होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इतना ही नहीं जिन लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, उनमें से कोई भी याचिकाकर्ता के साथ नहीं आया।दरअसल याचिकाकर्ता के साथ न केवल याचिकाकर्ता बल्कि महिला सहित तीन अन्य व्यक्ति जो गैर-मुस्लिम हैं, को भी अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसफर किया गया।

9 से 10 वर्षों से अधिक समय से रतलाम में उसका बने रहना और किसी भी तरह से, यहां तक कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाकर भी उक्त स्थान से बाहर जाने की उसकी अनिच्छा केवल उसके स्थानांतरण को रोकने के उसके हताश प्रयास को प्रदर्शित करती है, जो अत्यधिक निंदनीय है।

कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन

पटवारी बोले- जनता के खून-पसीने का पैसा था, जो इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया

इंदौर (एजेंसी)। नगर निगम में घोटाले के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने कमिश्नर ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदर्शन के दौरान कहा आपके (जनता) के खून-पसीने का पैसा था, जो इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आपसे वोट लिए, फिर आपके पैसे को लूट लिया। ये कैसा शहर, कैसा प्रदेश है। कहा ये जाता है कि पढ़ा-लिखा महापौर चुना है, ये कैसा महापौर है? पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने कहा निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने इंदौर के महापौर को एक्सीडेंटल महापौर बताया। पटवारी ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि 25 साल का कोई युवक नशा लेकर आता है तो वह कहां से आता है, इसकी दोषी 25 साल से सत्ता में बैठी

भाजपा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था नशे के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, थोड़े दिन उनको जोश आया था, उसके बाद वो सो गए।

सौरभ की जमानत पर कहा उसे बचाया जा रहा, सब मिले हैं- पटवारी ने सौरभ शर्मा की जमानत पर कहा कि उसे बचाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के सारे नेता उसमें मिले हुए हैं। जो डायरी थी, वह कहां गई और लोकायुक्त चुप है? 60 दिन में चालान पेश नहीं किया गया। दलबदलू के लिए पार्टी में जगह नहीं - पटवारी बोले कि जितने भी दलबदलू नेता हैं, जो धोखा देकर गए हैं उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। जो लोग नए हैं, उनका कांग्रेस में स्वागत है। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीतसिंह चड्ढा, सदाशिव यादव, चिंटू चौकसे, विनय बाकलीवाल, राजेश चौकसे, गिरधर नागर, अनिल यादव, विजय राठौर बंटी, नीलभ शुक्ला, अमित चौरसिया, मजहर सेठजीवाला, सोनिला मिमरोट आदि मौजूद थे।

फोटोग्राफर ने किया सुसाइड

प्रेमिका को मैसेज किया तेरी जिंदगी से दूर जा रहा हूं, तुम खुश रहना और फांसी लगा ली

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में प्रेम प्रसंग और आर्थिक तंगी के कारण दो युवकों ने आत्महत्या कर ली। पहला मामला परदेशीपुरा इलाके का है, जहां 25 साल के फोटोग्राफर मोहित बैरवा ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने अपनी प्रेमिका को एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था -तुम खुश रहना बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं।- मोहित के परिवार का कहना है कि वह पिछले 13 सालों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन हाल ही में वह एमवाय

अस्पताल के एक डॉक्टर से बात करने लगी। इसको लेकर मोहित और युवती के बीच विवाद हुआ और उसने शादी से इनकार कर दिया। इससे दुखी होकर मोहित ने बुधवार रात अपने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगा ली। शाम से ही उसके दोस्त उसे फोन कर रहे थे, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। जब रात 11 बजे दोस्त तुषार उसके घर पहुंचा, तो उसने मोहित को फंदे पर लटका देखा। मोहित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

संपादकीय

लोक परिवहन : सही फैसला

मप्र की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश में 20 साल बाद लोक परिवहन सेवा फिर से प्रारंभ करने के फैसले से प्रदेश की उस 6 करोड़ आबादी को बड़ी राहत मिलेगी, जो गांवों में रहती है और दूरदराज के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी दुर्लभ है। हालांकि नई सेवा पुरानी राज्य सड़क परिवहन निगम से थोड़ी अलग होगी। इसे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा नाम दिया गया है। यह आधुनिक और हाई टेक सेवा होगी। योजना के तहत ग्रामीण और साधारण मार्गों पर संगठित बस परिवहन सेवा को विकसित करने के लिए निजी बस ऑपरेटर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत लागू की जाएगी, जिससे बस संचालन, अधोसंरचना निर्माण और विनियमन में पारदर्शिता आएगी। कैबिनेट ने शुरुआती तौर पर इस काम के लिए 101 करोड़ रु. मंजूर किए हैं। बस संचालन के लिए प्रदेश में सात संभागीय कंपनियां बनाई जाएंगी। इनकी आईटी प्लेटफॉर्म से निगरानी होगी और इसके लिए ई-बस व चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवीज) कंपनियां कार्यरत हैं। इनमें से 16 कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि चार कंपनियां निष्क्रिय हैं। इन सभी को सात संभागीय कंपनियों में विलीन किया जाएगा। इन सभी कंपनियों का संचालन राज्य स्तरीय एक होल्डिंग कंपनी करेगी। सभी सातों कंपनियों के कार्यालयों में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बस, ऑटो, टैक्सी, ई-स्कूटर और मेट्रो सेवाओं को एकीकृत करने के लिए ट्रैवल ऐप तैयार किया जाएगा। इन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग समितियां बनेंगी। बसों का रूट सरकार तय करेगी लेकिन संचालन प्राइवेट ऑपरेटर करेंगे। एक हफ्ते पहले प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने नई व्यवस्था का प्रेजेंटेशन हो चुका है। बताया जाता है योजना के तहत पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इसमें तीन कैटेगरी की बसें शामिल होंगी। इसके लिए केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। गौरतलब है कि घाटे का तर्क देकर जिस मप्र राज्य परिवहन निगम को 2005 में बंद करने का फैसला तत्कालीन बाबूलाल गौर सरकार ने किया था, उसके मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। यही वजह है कि निगम को बंद करने की अधिकृत अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई। बंद करते समय निगम पर 1033 करोड़ रु. की देनदारियां थीं और 167 कर्मचारी काम कर रहे थे। सपनि के पास अभी भी 29 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे कॉमर्शियल उपयोग के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है। ऐसे में सरकार पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर सकती है। हालांकि, अभी सहमति बनना बाकी है। जिस कंपनी को बस स्टैंड देंगे, वह उसके कुछ हिस्से का कॉमर्शियल उपयोग कर सकेगी। हालांकि सरकार की नई परिवहन व्यवस्था को लेकर सड़क परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी और प्राइवेट ऑपरेटर्स का कहना है कि इससे आम जनता को नुकसान होगा। यात्री सेवा परिषद् के अध्यक्ष और सड़क परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि सरकार यदि सड़क परिवहन निगम को शुरू करती है तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कंपनियों के भरोसे बस संचालन जनता के साथ धोखा होगा। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि यदि सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ बदलाव करना है तो पुराने और अनुभवी मोटर मालिकों से बात करना चाहिए। यहां मूल मुद्दा तो परिवहन सेवा के सुगम और कुशल प्रबंधन का है। सपनि बंद होने का मुख्यल कारण भ्रष्टाचार और अकुशल प्रबंधन था। कहते हैं कि एक बस के पीछे तब 14 कर्मचारी थे। इसे रोकना होगा और बसों का संचालन व्यावसायिक कुशलता के साथ करना होगा, तभी यह योजना सफल होगी।

बुजुर्गों के एकाकीपन भी है नीतिगत मसला

नज़रिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

भारत अपने युवा-आबादी पर गर्व कर रहा है। चीन और भारत में जनसँख्या की अपनी ताकत है लेकिन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या से जहाँ ये देश अपनी शक्ति पर इतरा रहे हैं, वही आने वाले दिनों में सबसे बड़ा संकट भी बन्ने जा रही है। आज जब 60 प्रतिशत आबादी युवाओं की है और अब भारत में जागरूकता के कारण बच्चे कम करने के पक्ष में दम्पत्तियां आगे आई हैं तो आने वाले समय में 2050 तक यही आबादी बुजुर्ग जनसँख्या से भी अपने संकट का रोना रोएगी। चीन में चीजें दूसरी तरह की हैं। चीन का जनसंख्या प्रबंधन और उसकी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी सब भारत की अपेक्षा बहुत ठीक है। भारत में वैसी पॉलिसीज व नियोजन का अभाव है आज और आने वाले समय में बढ़ने वाला है, यह बड़ा संकट है।

भारत में बुजुर्ग आज उतने नहीं हैं जितने आगामी पच्चीस-तीस वर्ष बाद होंगे। बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के विकास व जीवनोल्लास के लिए समर्पित कर दिया वे अब उपेक्षा के शिकार हो हैं। परिवार में उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अपने ही घर के बच्चों से मिल नहीं पते बुजुर्ग। उन्हें घरों से उनकी संतानों द्वारा निकाल दिया जा रहा है। दिल्ली में बुजुर्गों के रख-रखाव के लिए आश्रय खुल रहे हैं जो इन बुजुर्गों को बुढ़ापे के समय रखने हेरू सालाना अच्छी खासी रकम ले रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की आज बातें देश में तेजी से हो रही हैं और बूढ़े लोग किस ज्ञान परंपरा के कारन उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, यह सोचनीय है। इसमें इन बुजुर्गों के सपनों और ऊंची सोच के भी खामियाजे सामने आ रहे हैं। ये बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु कान्वेंट में पढ़ाई-लिखाई करवाए। वे अपनी पीढ़ी में अपने सपने को साकार कर लेने की इच्छाशक्ति से कभी मुक्त नहीं हुए। इन बुजुर्गों के बच्चे अमेरिका, लन्दन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और अन्य विदेशी शिक्षालयों में शिक्षा लिए और वहीँ नौकरी ढूँढ़कर खुद की ज़िन्दगी को खुद तक सीमित करने की अपनी इच्छाशक्ति को लंबी उड़ान दी। अब जब उनके बच्चे उन्हें सेवा करने से मना कर रहे हैं तो ये बुजुर्ग निराशा में हैं।

विदेशी शिक्षा व संस्कृति में जीने वाले केवल उन्हीं बच्चों द्वारा ये बुजुर्ग उपेक्षित नहीं हैं बल्कि भारत में रह रहे बच्चे भी अपने बुजुर्गों से मुक्ति चाहते हैं। वे इनके साथ रहने पर खुद को अभिशप्त समझ रहे हैं। भारत के बुजुर्गों के लिए यह अभिशप्त काल है और आने वाले वर्षों में यह समस्या और बढ़ने वाली है। दिली जैसे मैट्रोपोलिटन शहरों में नोएडा, गुरुग्राम यानि गुड़गाँव ये एनसीआर के इलाके में रह रहे बड़ी इमारतों

में बुजुर्गों का एकाकीपन बढ़ रहा है। बच्चे अपने माँ-पिता से अलग रह रहे हैं। पहले बच्चों की रसोई बनती है उसके बाद बूढ़े माँ-पिता अपना खाना जैसे-तैसे बनाकर खाते और जीते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे कई थे लेकिन उनमें से कोई कहीं बस गया कोई कहीं बस गया। बूढ़े माँ-पिता एनसीआर के किसी फ़्लैट में हैं। उनके हारी-बीमारी में कोई साथ रहने वाला नहीं है। उनके दुःख-तकलीफ पर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। यह भारतीय संस्कृति बहुत बेचैन कर देने वाली है। यह भारत की स्थिति का दारिद्र्य कदाचित असह्य सा है।

वृद्धावस्था, जिसका सभी के मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायोग का अनुमान है कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 2050 में दोगुनी होकर 1।5 बिलियन हो जाएगी। 2050 तक, दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। भारत निश्चय ही एक बड़ी चुनौती की ओर बढ़ रहा है चाहे मानें या न मानें। एक ऐसा देश जिसमें वृद्धों की सेवा को शास्त्र में सर्वोत्तम सेवा माना गया है, उसी देश में वृद्धजन कष्ट और अवसाद में जीने को मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति ऐसा भी नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्र की समस्या है अपितु यह गाँव, वन-क्षेत्र में भी रहने वाली आदिवासी वृद्धों की भी समस्या है। हमारे ही गाँव के मिश्रा जी जिन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। उनका एक बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और दूसरा एनसीआर में रहता है। अमेरिका वाला गाँव आने वाला नहीं है। एनसीआर में रहने वाले ने विगत कुछ समय पहले आकर उनसे सभी जमीन अपने नाम लिखवा लिया और अब वह उन्हें अपने हालात पर बीमार अवस्था में छोड़कर चला गया। अपने ही बुजुर्गों को खुद सेवा नहीं करके उनके लिए एक मेडिकल केयरटेकर रख दिया है। नौकरी करने वाले लोग तो पेंशन पाते हैं, वे मेडिकल केयरटेकर या निजी चिकित्सक रख लेंगे लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, वे क्या करेंगे? यह बहुत बड़ी समस्या भारतीय समाज में घर करने जा रही है जहाँ लगाव माता-पिता और बच्चों के बीच से गायब हो जाएगा और एकाकीपन व अवसाद में बुजुर्ग जाने को मजबूर होंगे। अपने ही बच्चों पर नाज करने वाले, अपने बच्चों की गाँव में घूमकर तारीफ करने वाले लोग असहाय होकर जीवन जी रहे हैं, यह इसी भारत में हो रहा है।

वृन्दावन में अनिरुद्धाचार्य ने देश की सैकड़ों बुजुर्ग माताओं को आश्रय दिया है। सेवा व सुश्रुषा कर रहे हैं। यहाँ पहुँची माताएं अपनी-अपनी दर्द भरी कहानी हैं। लेकिन दिल्ली और दूसरे शहरों में जिसके बारे में एक ऑटो वाले ने बताया कि उसके दूर के मामा ने अपनी माँ को बुजुर्ग के लिए पांच लाख रूपये सालाना पेड ओल्ड एज हाउस में छोड़कर गए। मैं अपनी नानी को घर लाया हूँ। उनकी मैं सेवा करता हूँ और वह हमारे बच्चे के साथ खेलती हैं, मुझे अच्छा लगता है। उसके अनुसार उसके मामा ने सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और माँ को पेड ओल्ड एज होम छोड़ गए थे, वहां मेरी नानी दुखी रहती थीं। यह भारत की पीड़ा देने वाली कहानियां भारत के भविष्य की चुनौतियों को हमें केवल बता नहीं रही हैं अपितु उनसे लड़ने और आवश्यक पॉलिसीज तैयार कर बुजुर्गों के अवसाद से बचने और इसके साथ आने वाली दूसरी मानव अधिकार की समस्याओं से निजात पाने का आग्रह कर रही हैं। हाल ही में आईआईटीएन बाबा के दिए गए इंटरव्यू में अपने माँ-पिता के प्रति असंवेदनशीलता से पूरा भारत परिचित हुआ है। उनका तर्क यह है कि वे अपने घर में क्यों रहना चाहते हैं और वह वानप्रस्थ कब करेंगे? वे अब अपना जीवन जी चुके हैं, अब और क्यों जीने के लिए इच्छा रखते हैं? यह सब इस भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने एक बार कहा था कोई भी समाज वृद्ध लोगों की बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और अनुभव को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। वृद्ध लोगों को उनके सामने आने वाली अनूठी मानवाधिकार चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए।

ये वृद्धजन जीवन के इस छोर पर अपने लिए केवल सम्मान, दो जून का भोजन और ज़रूरी इलाज चाहते हैं। ये बुजुर्ग जिस देश के नागरिक हैं, वे उस देश से अपने जीवन के इस दहलीज पर ऐसे कुछ प्रावधान चाहते हैं, जिससे उनके अपने ही लोग उनकी धन संपत्ति को न छीन सकें। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज में संवेदनाएँ समाप्त हो रही हैं। आत्मीयता समाप्त हो रही हैं। बुजुर्ग लोग ऐसे में किसका आश्रय लें, यह उनकी समझ से बाहर है। चिंताजनक यह है कि सरकार व समाज के ही लोग समय रहते कब इस पर सोचेंगे, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है और बुजुर्ग-जन के एकाकीपन प्रत्येक दिन भारी पड़ रहे हैं। इसका हल यदि निकालने के प्रयास हों, तभी हम भारतीय संस्कृति और वृद्धजन को बचा सकेंगे।

कांचा गचीबोवली : विकास के नाम पर विनाश का वर्चस्व

पर्यावरण

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में स्थित कांचा गचीबोवली गाँव में भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस भूमि को अपनी संपत्ति घोषित करते हुए इसे विकसित करने की योजना बनाई है, जबकि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरणविद इस भूमि को संरक्षित करने की माँग कर रहे हैं। यह विवाद केवल भूमि अधिग्रहण का नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, कानूनी विवादों और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है।

तेलंगाना सरकार ने कांचा गचीबोवली में लगभग 400 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भूमि को सरकार द्वारा विकसित कर आईटी पार्क, शहरी जीवन क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीलाम किया जाना प्रस्तावित है। सरकार को इस नीलामी से लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह भूमि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व की है और इसे किसी भी प्रकार से वन क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र नहीं माना जा सकता।

सरकार के अनुसार, यह भूमि औद्योगिक और शहरी विकास के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, टीजीआईआईसी (तेलंगाना राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम) ने इस भूमि का निरीक्षण कर इसे विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना में मशरूम रॉक और अन्य प्रमुख प्राकृतिक संरचनाओं को संरक्षित रखते हुए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिससे विकास और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरणविदों का कहना है कि यह भूमि केवल एक खाली क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह विभिन्न जैव विविधताओं से भरपूर एक प्राकृतिक क्षेत्र है। 2008-09 में हैदराबाद विश्वविद्यालय और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर -इंडिया द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र में 455 से अधिक प्रजातियों के वनस्पति और जीव-जंतुओं का निवास है। इनमें दुर्लभ वनस्पतियाँ, तितलियाँ, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने इस भूमि को बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और उचित पर्यावरणीय मंजूरी के हटाना शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुँचेगी।

रविवार को जब सरकार ने इस क्षेत्र को समतल करने के लिए 50 से अधिक भारी मशीनें तैनात कीं, तो छात्रों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने विरोध कर रहे 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिससे छात्र समुदाय में आक्रोश फैल गया। छात्रों का कहना है कि यह भूमि जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नष्ट करना पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकता है।

इस भूमि को संरक्षित करने के लिए छात्रों और पर्यावरणविदों द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है, लेकिन सरकार ने इसके पहले ही यहाँ भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि रातों-रात 50 से अधिक जेसीबी मशीनों द्वारा इस क्षेत्र को समतल किया गया, जिससे वहाँ की वनस्पति और जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हुई।

छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाड बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो उसे 'वन क्षेत्र' माना जाएगा, भले ही वह सरकारी रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित न हो। इस संदर्भ में, यह भूमि प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्र की श्रेणी में आती है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

सरकार ने अपने रुख पर कायम रहते हुए स्पष्ट किया है कि यह भूमि किसी भी प्रकार से वन क्षेत्र नहीं है और पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह 2006 में 'एमएस आईएमजी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड' से वापस ली गई थी और इसे औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित था। सरकार ने यह भी कहा कि उसने विश्वविद्यालय की किसी भी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है और वहाँ के किसी भी जल स्रोत या प्राकृतिक संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाया है।

सरकार ने यह भी तर्क दिया कि यह भूमि केवल सरकारी राजस्व भूमि है और इसे औद्योगिक तथा शहरी विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र का उपयोग हाई-टेक सिटी के विस्तार के लिए किया जा सकता है, जिससे आईटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2024 में राजस्व विभाग द्वारा इस भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और विश्वविद्यालय ने इस भूमि के सीमांकन पर कोई सहमति नहीं दी है। विश्वविद्यालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और छात्रों द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों पर गौर करना चाहिए। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस भूमि के हस्तांतरण के लिए कार्यकारी परिषद की सहमति आवश्यक है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्यों से मिलकर बनी होती है।

इस पूरे विवाद में केवल कानूनी और प्रशासनिक पहलू ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी गहरे हैं। यदि इस क्षेत्र का विकास किया जाता है, तो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होगा। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक जंगल और जैव विविधता का घर है, जिसका विनाश आगे चलकर पूरे हैदराबाद शहर के जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, छात्रों और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह भूमि न केवल पर्यावरणीय बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। कई दशकों से यह क्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधकर्ताओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

कांचा गचीबोवली का भूमि विवाद केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक जागरूकता का भी प्रश्न है। सरकार इस भूमि को विकसित कर औद्योगिक और शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहती है, जबकि छात्र और पर्यावरणविद् इसे संरक्षित रखने की माँग कर रहे हैं।

इस जटिल स्थिति का समाधान सभी हितधारकों के बीच संवाद और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से ही संभव है। कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करे ताकि इस पर विवाद की स्थिति स्पष्ट हो। यदि विश्वविद्यालय या स्थानीय समुदाय इस पर दावा करते हैं, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए, जिससे कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। भूमि अधिग्रहण संबंधी सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

संवाद आधारित समाधान इस विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार को स्थानीय समुदाय, विश्वविद्यालय प्रशासन और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि संतुलित समाधान निकाला जा सके। एक संयुक्त समिति गठित की जा सकती है, जो इस भूमि की ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्ता का अध्ययन करे और उसके आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार करे। यदि भूमि का कोई हिस्सा पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है, तो उसे संरक्षित करने की पहल की जानी चाहिए, जबकि अन्य भाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकता है।

पर्यावरण की दृष्टि से यदि इस भूमि पर जैव विविधता या पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र को 'अर्बन फॉरेस्ट' या 'ग्रीन ज़ोन' घोषित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। यदि विकास अपरिहार्य हो, तो 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' मॉडल को अपनाते हुए हरियाली और जल-संरक्षण जैसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार, यदि यह भूमि ऐतिहासिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इस विवाद के समाधान के लिए सरकार को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जहाँ विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों का समुचित ध्यान रखा जाए। यह विवाद केवल भूमि के स्वामित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शी और समावेशी नीति अपनाए, जिससे सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके। किसी एक पक्ष के हितों की अनदेखी करना दीर्घकालिक रूप से न्यायसंगत नहीं होगा, इसलिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर एक टिकाऊ समाधान खोजा जाना चाहिए।

छोटे और सजग प्रयासों पर टिका परिवर्तन

चिंतन

श्वेता गर्ग

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या वाकई युग बदल गया है, हम बदल गए हैं,माता पिता बदल गए हैं या बचपन बदल गया है? पर कुछ न कुछ तो ज़रूर बदला है हम समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते! गत दिनों नेटफ्लिक्स पर बहुचर्चित सीरीज 'एडोलेसेंस' देखने का मौका मिला, जो एक चौंका देने वाले रहस्यमयी अपराध की जांच के आगे पीछे घूमती हुयी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता में यह सीरीज आज के डिजिटल युग में समाज में चल रहे बच्चों के पालन पोषण के तरीके, और मानसिक स्वस्थ्य के बारे में झांकने के साथ साथ हमें कई मूल्यवान सबक भी देती है। साथ ही भारतीय समाज को भविष्य का आईना भी दिखाती हुई प्रतीत हुई कि अभी भी वक़्त है संभल जाइये। आमजन कहते हैं ऐसा विदेशों में होता है भारत में नहीं।

मेरा सौभाग्य है कि मेरा प्रतिदिन 8 घंटे का समय एक विद्यालय में बच्चों और पालकों के बीच ही व्यतीत होता है। पालकों की व्यस्तता जिस गति से बढ़ रही है उनकी अपने बच्चों से अपेक्षाएं उसी गति से बढ़ रही हैं। माता पिता को बच्चों से बात करने का समय नहीं है।बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का जिम्मा भी स्कूल में उपलब्ध काउंसलर पर डाल दिया गया है। परन्तु माता पिता अपने बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर जितना ध्यान दे सकते है क्या कोई स्कूल काउंसलर डेढ़ दो हजार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी उतनी कुशलता से कर सकता है?

साथ ही भारत में भी यदि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध विषाक्त सामग्री, अवास्तविक सौंदर्य मानकों और हानिकारक विचारधाराओं से बचपन को दूर नहीं किया गया तो भयंकर परिणाम सामने आएंगे। आज के अंधे और आपाधापी वाले दौड़ते युग में, माता पिता और बच्चों के बीच खुले संवाद की बहुत आवश्यकता है जिससे बच्चे अपने परिवार से जुड़े रह सकेंगे। आदेशात्मक समाज का अंत हो चुका है और तथ्य आधारित बातचीत का आजकल के बच्चे हमेशा स्वागत करते हैं। यह हम सब जितनी जल्दी समझ ले उतना ज्यादा अच्छा है।

इंटरनेट पर अप्रतिबंधित पहुँच बच्चों को खतरे में डाल रही है अतः सभी पालक स्क्रीन टाइम को सीमित करें, सिर्फ बच्चों का नहीं, अपितु अपना स्वयं का भी। किशोरावस्था के लड़कों को भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है ये समझना भारतीय समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। 'लड़का है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा' वाली सोच से सबको बाहर आना होगा।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन दबाव के कारण बच्चे चिंता और अवसाद में जीने लग जाते हैं इसलिए पालकों को बेहद सजग रहने की ज़रूरत है कि बच्चे में किशोरावस्था में जो बदलाव हो रहे हैं वो प्राकृतिक हैं या नहीं? इसके लिए यदि किसी पेशेवर की मदद लेनी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप अपने बच्चों से जुड़े रहें और बच्चों को विश्वास में लें कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की बातचीत अथवा सहायता की आवश्यकता महसूस हो तो वे सबसे पहले आप के पास आएं, और आप उनकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे।

ऐसे ही छोटे छोटे और सजग प्रयासों पर आधारित परिवार की संरचना कीजिए और अपने बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते देखिए।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नोटों का काम जलना नहीं जलाना है

व्यंग्य

सुदर्शन कुमार सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

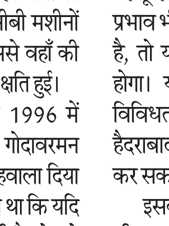

दिल्ली में एक न्यायधीश महोदय के बंगले में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब इसने आग पर काबू पाया तो कई बोरियों में अधजले नोट पाए गए। जज साहब का कहना है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तो दूसरे दिन ऐसे कोई नोट नहीं मिले। फिर उनका कहना था कि जहां ये घटना हुई उस जगह को एक अलग दीवार उनके बंगले से अलग करती है। दिल्ली पुलिस भी गजब की है इसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को इसका वीडियो भेज दिया। वहां और गजब हुआ वीडियो पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। अब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात तो है कि जहां आग लगती है वहीं धुंआ उठता है। ये धुंआ कोई ऐसा वैसा धुंआ नहीं बोरियों में भरे रहस्यमय नोटों पर लगी आग का धुंआ है। नोटों पर तो बिना माचिस लगाए आग नोटबंदी में भी लगी थी ऐसी कि लोग स्वेच्छा से जलाने तैयार हो गए थे। बहुतों ने 'ओम रूपया नमः स्वाहा' की सहस्त्र आहुतियां दी थीं। इस दौरान जन धन योजना के खाते बड़े काम आए थे। सरकार ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ड्रीम योजना के खातों में उससे ज्यादा डीबीटी आखिरी कमाई वाले करेंगे।

नोट बंदी को तो छोड़ो। गंगाधर का अधजले नोटों पर एक अलग ही विचार है। दोषी तो यहां जज साहब या कोई और नहीं है। नोट स्वयं ही हैं। नोटों का काम जलना नहीं जलाना है। यह अपना मूल स्वभाव भूल गया। नोटों का भी चारित्रिक पतन पतनशील लोगों के हाथों अकूत काला धन आने से हुआ है। सीने में बापू की फोटो के बावजूद इतनी जल्दी समझौता कर डाला। नोट तो दूसरों के दिलों दिमाग में आग लगाते हैं। ये स्वयं होम हो गए। फायर ब्रिगेड कम से कम मध्यांतर में आ तो जाता है नहीं तो पुलिस होती तो आखिरी में आती। अरे राख ही बन जाने देते तो आरोपों की इतनी राख तो नहीं उड़ती।

नोट तरह-तरह से लोगों को जलाता है। आप कुछ लोग दो कमरे के छोटे से मकानों में गुजर बसर करते हैं। लेकिन कोई एक धन्ना सेठ यानि कि नोटों से भरपूर आदमी कहीं से आया। पास की जमीन खरीद अपनी कोठी तनवा डाली। आसपास के सबको जला डाला। ये नोटों की ही तो माया थी। कुछ लोग तो दूसरों की प्रगति पर इतना जलते हैं कि उस पर तो रोटी सेकी जा सकती है।

प्रेमिका पर यदि प्रेमी अच्छी खासी रकम खर्च करता रहे तो वो मुहब्बत की आग में जलने लगती है। ये मुहब्बत की आग आखिर लगाई किसने अरे वही खरे-खरे नोटों ने। विश्वास नहीं है तो मुझे एक उदाहरण दे दो कि साइकल पर चलने वाले किसी प्रेमी ने कभी प्रेमिका के दिल पर आग लगाने में कामयाबी पाई हो। ऐसा प्रेमी ब्रेकअप में कामयाबी पाता है। कभी नहीं केवल हिन्दी सिनेमा को छोड़कर। असल में तो वो ऐसे बालमा पर आग बबूला होती है।

नोटों का डीएनए जलाने का होता है। अरे सुकून से आप आलीशान कोठी, लग्जरी कार व महंगे आभूषणों के रूप में दूसरों को जलाते। लेकिन आपको तो इतनी जल्दी कि स्वयं ही जल उठे। पतंगे का तो सुना था कि दीपक की ओर भागता है। इतनी जल्दी तो नितीश कुमार जी भी पाला नहीं बदलते।

अरे नोट महाराज आप तो इतनी तरह से लोगों को जलाते रहते हो कि उसका वर्णन करने निकले तो जगह कम पड़ जाएगी। अभी ईशा अंबानी ने कोई एक ड्रैस पहनी दस लाख की आपकी ही दम पर। तो न जाने कितनी सुंदरियां भीतर ही भीतर ऐसी किस्मत देख जल उठी होंगी।

आपकी महिमा अपरंपार। मुकेश अम्बानी ने अपने सुपुत्र की शादी में दिल खोल के नोट खर्च किये कि चार माह तक कार्यक्रम का कवरेज मीडिया में आता रहा। न जाने कितने कितने लोगों को यहां के ठाठ-बाट से जलन हो उठी होगी। बताईये आप जले कि आपने जलाया। फिर उन्होंने जियो की दर बढ़ाने का 'मेरा सपना सबका अपना' को 'मेरा सपना मेरा अपना' में बदल रातों रात दर बढ़ा विवाह का पूरा पैसा वसूल लिया। सही है न जिसके पास आपका समृद्ध सान्निध्य हो उसका दिमाग भी खूब चलता है।

चलते-चलते एक ही सवाल आपके डीएनए में ये अनपेक्षित उत्परिवर्तन हुआ आखिर कैसे? क्या जरूरत थी जलने की वो भी आधे अधूरे मन से।

जयंती पर विशेष

प्रो.संजय द्विवेदी

(लेखक मा. च. राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल में प्राध्यापक हैं।)

भारतीय पत्रकारिता के 'कर्मवीर' पं. माखनलाल चतुर्वेदी

पं. माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में निकला 'कर्मवीर' एक ऐसा पत्र है, जिसकी धमक हम आज भी महसूस करते हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 'कर्मवीर' एक ऐसा नाम है, जिसे छोड़कर भारतीय पत्रकारिता का समग्र मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसी तरह उसके संपादक पं. माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी संपूर्ण जीवनयात्रा, आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले संपादक की यात्रा है। रचना और संघर्ष की भावभूमि पर खड़ी हुयी उनकी लेखनी में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का जज्बा न चुका, न कम हुआ। वस्तुतः वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे और कोई मोर्चा ऐसा न था, जहां उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। सही मायने में 'कर्मवीर' के संपादक ने अपने पत्र के नाम को सार्थक किया और माखनलाल जी स्वयं कर्मवीर बन गए। 4 अप्रैल, 1889 को होशंगाबाद (मप्र) के बाबई जिले में जन्में माखनलालजी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखा जा रहा था। इसी के साथ महात्मा गांधी जैसी तेजस्वी विभूति के आगमन ने सारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। दादा माखनलाल जी भी उन्हीं गांधी भक्तों की टोली में शामिल हो गए। गांधी के जीवन दर्शन से अनुप्राणित दादा ने रचना और कर्म के स्तर पर जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा एवं गति दी वह महत्व का विषय है।

पत्रकारिता का गांधी समय

इस दौर की पत्रकारिता भी कमोबेश गांधी के विचारों से खासी प्रभावित थी। सच कहें तो हिंदी पत्रकारिता का वह जमाना ही अजीब था। आम कहावत थी- जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और सच में अखबार की ताकत का अहसास आजादी के दीवानों को हो गया था। इसी के चलते सारे देश में आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने पत्र निकाले। इस दौर में अखबारों का इस्तेमाल एक अस्त्र के रूप में हो रहा था और माखनलाल जी का 'कर्मवीर' इसमें एक जरूरी नाम बन गया था।

हालांकि इस दौर में राजनीतिक एवं सामाजिक पत्रकारिता के समानांतर साहित्यिक पत्रकारिता का एक दौर भी चल रहा था। सरस्वती और उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके प्रतिनिधि के रूप में उभरे। माखनलाल जी ने भी 1913 में प्रभा नाम की एक उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से इस क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप किया। दादा की 56 सालों की ओजपूर्ण पत्रकारिता की यात्रा में प्रताप, प्रभा व कर्मवीर उनके विभिन्न पड़ाव रहे। साथ ही उनकी राजनीतिक वरीयता भी बहुत ऊंची थी। वे बड़े कवि थे, पत्रकार थे पर उनके इन रूपों पर राजनीति कभी हावी न हो पायी। आजादी के बाद 30 अप्रैल, 1968 तक वे जीवित रहे, पर सत्ता का लोभ उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं 1967 में भारतीय संसद द्वारा राजभाषा विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को वह पद्मभूषण का अलंकरण भी लौटा दिया जो उन्हें 1963 में दिया गया था। उनके मन में संघर्ष की ज्वाला हमेशा जलती रही। वे निरंतर समझौतों के खिलाफ लोंगों में चेतना जगाते रहे। उन्होंने स्वयं लिखा है-

अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली

यह सुधार-समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। माखनलाल जी सदैव असंतोष एवं मानवीय पीड़ाबोध को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्वर देते रहे। माखनलाल जी 'कर्मवीर' के संपादक कैसे संपादक थे, इसे बताने के लिए उन्होंने कहा कि - 'हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं। किसी की फरमाइश पर जूते बनाने वाले चर्मकार नहीं हैं हम।' यह निर्भीकता ही उनकी पत्रकारिता की भावभूमि का निर्माण करती थी। स्वाधीनता आंदोलन की आँच को तेज करने में उनका कर्मवीर अग्रणी बना। कर्मवीर जिस भाषा में अंग्रेजी राजसत्ता से संवाद कर रहा था, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनमानस में आजादी पाने की ललक कितनी तेज थी।

स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्रखर हस्तक्षेप के अलावा कर्मवीर ने जीवन के विविध पक्षों को भी पर्याप्त महत्व दिया। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति के अलावा साहित्य कला और संस्कृति को भी महत्व दिया। साहित्यिक पत्रों के संदर्भ में माखनलाल जी की समझदारी विलक्षण थी वो कहते हैं- 'हिंदी भाषा का मासिक साहित्य बेढंगे और बीते जमाने की चाल चल रहा है। यहां बरसाती कीड़ों की तरह पत्र पैदा होते हैं। फिर भी यह आश्चर्य नहीं कि वे मर क्यों जाते हैं। यूरोप में हर पत्र अपनी एक निश्चित नीति रखता है। हिंदी वालों को इस मार्ग में रीति की गंध नहीं लगी।' यह टिप्पणी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।

अपने लंबे पत्रकारीय जीवन के माध्यम से दादा ने नई पीढ़ी को रचना और संघर्ष का जो पाठ पढ़ाया वह आज भी हतप्रभ कर देने वाला है। उनके संपादकीय कार्यालय यानी घर पर तिरसठ बार छापे पड़े, तलाशियां हुयीं। 12 बार वे

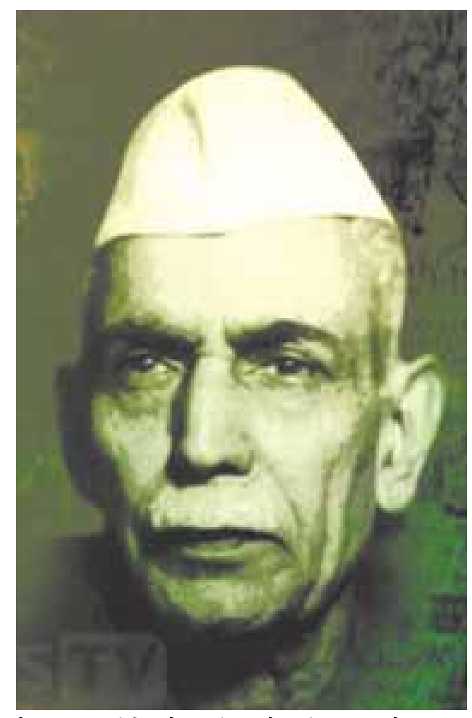

जेल गए। कर्मवीर को अर्थाभाव में कई बार बंद होना पड़ा। लेखक से लेकर प्रूफ रीडर तक सबका कार्य वे स्वयं कर लेते थे। इन अर्थों में दादा विलक्षण स्वावलंबी थे।

पत्रकारिता के मूल्य और राष्ट्र प्रथम की नीति

कर्मवीर एक ऐसा पत्र था जिसके संपादक आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इसलिए राष्ट्र प्रथम उसकी वैचारिक नीति भी रही। आजादी के समय देश के बंटवारे का दंश पूरे देशवासियों के मनों को मथ रहा था। इस भावना को व्यक्त करते हुए 'कर्मवीर' के 15 अगस्त,1947 को माखनलाल जी लिखते हैं- 'यह 15 अगस्त है, भारत दो टुकड़े हैं, किंतु आजाद है, क्या पूर्ण आजाद है...? यह जवाहर और जयप्रकाश जानें कि भारत पूर्ण स्वतंत्र होगा या उपनिवेश बनकर रह जाएगा। नोआखली को जानेवाले यात्री गांधी से देश 'स्वागत' नहीं कह सकता, क्योंकि देश खंडित है। बिदा भी नहीं कह सकते क्योंकि अखंड भारत और पूर्ण स्वातंर्त्य का स्वप्न अभी अपनी मुठ्ठी में लिए वह चला जा रहा है। यह 15 अगस्त है।' भरतपुर के संपादक सम्मेलन में वे पत्रकारिता जगत का आह्वान करते हुए कहते हैं-'यदि समाचार पत्र संसार की एक बड़ी ताकत है तो उसके सिर जोखिम भी कम नहीं है। पर्वत की जो शिखरें हिम से चमकती हैं और राष्ट्रीय रक्षा की महान दीवार बनती हैं, उन्हें ऊंची होना पड़ता है। जगत में समाचार पत्र यदि बड़प्पन पाए हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी भारी है।बिना जिम्मेदारी के बड़प्पन का मूल्य ही क्या है?'

कर्मवीर अपने समय का एक ऐसा पत्र बना जिसने समकालीन रचनाशीलता को बहुत प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही अनेक बड़े लेखक जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रमाशंकर शुक्ल, भवानी प्रसाद तिवारी, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, वीरेंद्र जैन, शिवमंगल सिंह सुमन, धर्मवीर भारती ही नहीं दिनकर, रामबृक्ष बेनीपुरी, सोहनलाल द्विवेदी तक इसमें छपते रहे।

'कर्मवीर' की संपादकीय नीति

माखनलाल जी आम लोगों के बीच से उपजे पत्रकार थे। उनका कहना था कि पत्र संपादक की दृष्टि परिणाम पर सतत लगी रहनी चाहिए। क्योंकि वह समस्त देश के समक्ष उत्तरदायी है। वे समाचार पत्रों में उत्तरदायित्व की भावना भरना चाहते थे। वहीं उनके मन में समाचार पत्र की पूर्णता को लेकर भी विचार थे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पत्रों को ऐसा बनाना चाहिए कि हम पर ज्ञान की कमी का लांछन न लगे। वे पत्रकारिता जगत में फैल सकने वाले प्रदूषण के प्रति भी आशंकित थे। इसी के चलते उन्होंने अपने लिए आचार संहिता भी बनाई। आज जब पत्रकारिता और पत्रकारों के चरित्र पर सवालिया निशान लग रहे हैं तो यह सहज ही पता लग जाता है कि दादा वस्तुतः कितनी अग्रगामी सोच के वाहक थे। हिंदी पत्र साहित्य को उनकी एक बड़ी देन यह है कि उन्होंने कई तरह से हिंदी को मोड़ा और लचीला बनाया। भाषा को समृद्ध एवं जनप्रिय बनाने में उनका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। 4 अप्रैल,1925 को खंडवा से कर्मवीर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 'कर्मवीर' के संपादक के रूप में पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने संपादन-सिद्धांत बनाए और उन्हें घोषित किया जो इस प्रकार थे-

1. 'कर्मवीर' संपादन और 'कर्मवीर परिवार' की कठिनाइयों का उल्लेख न करना।
2. कभी धन के लिए अपील न निकालना।
3. ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए 'कर्मवीर' के कालमों में न लिखना।
4. क्रांतिकारी पार्टी के खिलाफ वक्तव्य नहीं छापना। (गांधीजी का वक्तव्य भी कर्मवीर में नहीं छपा था।)
5. सनसनीखेज खबरें नहीं छापना।
6. विज्ञापन जुटाने के लिए किसी आदमी की नियुक्ति न करना।

ये संपादकीय सिद्धांत कर्मवीर के तेवर को बताते हैं। आज के समय में इन सिद्धांतों पर चलकर पत्र प्रकाशन मुश्किल है। लेकिन माखनलाल जी ने ऐसा किया और गरिमा के साथ किया। आजादी के आंदोलन में वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे किंतु गरम दल के नेताओं और क्रांतिकारियों के प्रति उनकी सहानुभूति साफ दिखती थी। उनका मानना था कि अलग-अलग मार्ग से हम सभी भारत माता की मुक्ति के यज्ञ में योगदान दे रहे हैं, इसलिए क्रांतिकारियों के विरुद्ध कुछ भी कर्मवीर नहीं छापेगा। महात्मा गांधी स्वयं उनके इस संकल्प को जानते थे। राष्ट्रपिता ने इस महान पत्रकार के बारे में कहा-'हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना (भाषण) तो माखनलाल जी ही जानते हैं।' इतना ही नहीं राष्ट्रपिता ने कहा- 'मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वह माखनलालजी का जन्मस्थान है। जिस भूमि ने माखनलालजी को जन्म दिया, उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूं।'

पत्रकारिता विद्यापीठ के स्वप्नदृष्टा

माखनलाल जी ने ही देश में एक पत्रकारिता विद्यापीठ स्थापित करने का स्वप्न देखा था। उन्होंने भरतपुर(राजस्थान) में 1927 में आयोजित संपादक सम्मेलन में कहा था-'हिंदी समाचार पत्रों में कार्यालय में योग्य व्यक्तियों के प्रवेश कराने के लिए, एक पाठशाला आजकल के नए नामों की बाढ़ में से कोई शब्द चुनिए तो कहिए कि एक संपादन कला के विद्यापीठ की आवश्यक्ता है। ऐसी विद्यापीठ किसी योग्य स्थान पर बुद्धिमान, परिश्रमी, अनुभवी, संपादक-शिक्षकों द्वारा संचालित होना चाहिए। उक्त पीठ में अन्यान्य विषयों का एक प्रकांड ग्रंथ संग्रहालय होना चाहिए।' यह संयोग ही है कि उनके इस स्वप्न को 1990 में मध्यप्रदेश सरकार ने साकार करते हुए उनके नाम पर ही भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। 30 जनवरी,1968 को उनका निधन हो गया। आज जब पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर संकट के बादल हैं, पाठक एवं अखबार के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है ऐसे संक्रमण में कर्मवीर जैसे पत्रों और उसके यशस्वी संपादक की याद आना बहुत स्वाभाविक है।

पं. माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती विशेष

लोकेन्द्र सिंह

सहायक प्राध्यापक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

जब पत्रकारिता ने चलाया गो-संरक्षण आंदोलन

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उन विरले स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा को राष्ट्रीयता के जागरण एवं स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अपने लंबे पत्रकारीय जीवन के माध्यम से माखनलाल जी ने रचना, संघर्ष और आदर्श का जो पाठ पढ़ाया वह आज भी हतप्रभ कर देने वाला है। आज की पत्रकारिता के समक्ष जैसे ही गो-हत्या का प्रश्न आता है, वह हिंदुत्व और सेकुलरिज्म की बहस में उलझ जाता है। इस बहस में मीडिया का बड़ा हिस्सा गाय के विरुद्ध ही खड़ा दिखाई देता है। सेकुलरिज्म की आधी-अधूरी परिभाषाओं ने उसे इतना भ्रमित कर दिया है कि वह गो-संरक्षण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को सांप्रदायिक मुद्दा मान बैठा है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गो-संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना कोई टेड़ी खीर नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मीडिया गो-संरक्षण या गो-हत्या को हिंदू-मुस्लिम रंग देने लगता है। गो-संरक्षण शुद्धतौर पर भारतीयता का मूल है। इसलिए ही 'एक भारतीय आत्मा' के नाम से विख्यात महान संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी गोकशी के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर देते हैं। गोकशी का प्रकरण जब उनके सामने आया, तब उनके मन में द्वंद्व कतई नहीं था। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी- भारत के लिए गो-संरक्षण आवश्यक है। कर्मवीर के माध्यम से उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गो-संरक्षण की लड़ाई लड़ी और अंत में विजय सुनिश्चित की।

1920 में मध्यप्रदेश के शहर सागर के समीप रतौना में ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ा कसाईखाना खोलने का निर्णय लिया। इस कसाईखाने में केवल गोवंश काटा जाना था। प्रतिमाह ढाई लाख गोवंश का कत्ल करने की योजना थी। अंग्रेजों की इस बड़ी परियोजना का संपूर्ण विवरण देता हुआ चार पृष्ठ का विज्ञापन अंग्रेजी समाचार-पत्र हितवाद में प्रकाशित हुआ। परियोजना का आकार कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि लगभग 100 वर्ष पूर्व कसाईखाने की लागत लगभग 40 लाख रुपये थी। गो-मांस के परिवहन के लिए कसाईखाने तक रेल लाइन डाली गई थी। तालाब खुदवाये गए थे। कत्लखाने का प्रबंधन सेंट्रल प्रोविंसेज टेनिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ने अमेरिकी कंपनी सेंट डेविन पोर्ट को सौंप दिया था, जो डिब्बाबंद बीफ को निर्यात करने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति भी ले चुकी थी।

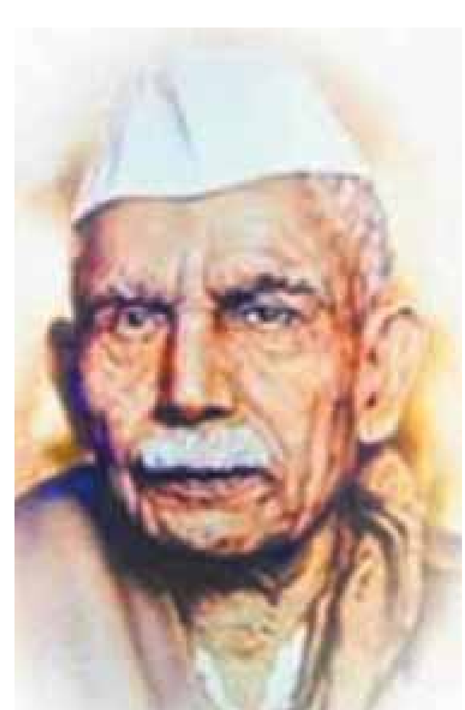

गोवंश की हत्या के लिए यह कसाईखाना प्रारंभ हो पाता उससे पहले ही दैवीय योग से महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने यात्रा के दौरान यह विज्ञापन पढ़ लिया। वह तत्काल अपनी यात्रा खत्म करके वापस जबलपुर लौटे। वहाँ उन्होंने अपने समाचार पत्र 'कर्मवीर' में रतौना कसाईखाने के विरोध में तीखा संपादकीय लिखा और गो-संरक्षण के समर्थन में कसाईखाने के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने का आह्वान किया। सुखद तथ्य यह है कि इस कसाईखाने के विरुद्ध जबलपुर के एक और पत्रकार उर्दू दैनिक समाचार पत्र 'ताज' के संपादक मिस्टर ताजुद्दीन मोर्चा पहले ही खोल चुके थे। उधर, सागर में मुस्लिम नौजवान और पत्रकार अब्दुल गनी ने भी पत्रकारिता एवं सामाजिक आंदोलन के माध्यम से गोकशी के लिए खोले जा रहे इस कसाईखाने का विरोध प्रारंभ कर दिया। मिस्टर ताजुद्दीन और अब्दुल गनी की पत्रकारिता में भी गोहत्या पर वह द्वंद्व नहीं था, जो आज की मीडिया में है।

दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में थी। इसलिए कसाईखाने के विरुद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की कलम से निकले आंदोलन ने जल्द ही राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया। देशभर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में रतौना कसाईखाने के विरोध में लिखा जाने लगा। लाहौर से प्रकाशित लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदेमातरम् ने तो एक के बाद एक अनेक आलेख कसाईखाने के विरोध में प्रकाशित किए। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का प्रभाव था कि मध्यभारत में अंग्रेजों की पहली हार हुई। मात्र तीन माह में ही अंग्रेजों को कसाईखाना खोलने का निर्णय वापस लेना पड़ा। आज उस स्थान पर पशु प्रजनन का कार्य संचालित है। जहाँ कभी गो-रक्त बहना था, आज वहाँ बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। कर्मवीर के माध्यम से गो-संरक्षण के प्रति ऐसी जाग्रती आई कि पहले से संचालित कसाईखाने भी स्वतः बंद हो गए। हिंदू-मुस्लिम सौहार्द्र का वातावरण बना सो अलग। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का यह प्रसंग किसी भव्य मंदिर के शिखर कलश के दर्शन के समान है। यह प्रसंग पत्रकारिता के मूल्यों, सिद्धांतों और प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

यह 'पत्रकारिता' का सौभाग्य था कि उसे दादा माखनलाल जैसा सुयोग्य संपादक प्राप्त हुआ, जिसने भारत की पत्रकारिता में 'भारतीयता' के भाव की स्थापना की। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय पत्रकारिता के ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं, जिनसे आज भी भारत की पत्रकारिता आलोकित हो सकती है।

दक्षिण की राजनीति

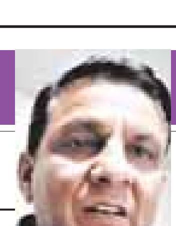

वेद विलास उनियाल

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक

फिर एक रथ पर सवार बीजेपी और अन्ना द्रमुक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्ना द्रमुक के महासचिव ई पलानीस्वामी की मुलाकात के बाद दक्षिण की सियासत को लेकर हलचल बढी। इसके पीछे तमिलनाडु की सियासत का वह परिदृश्य है जिसमें यह माना जा रहा है कि बेशक कई कारणों से डीएमके की छवि पर विपरीत असर पड़ा हो, लेकिन अभी बीजेपी के लिए अकेले दम पर उसकी सत्ता को हिलाना मुश्किल है। उधर, अन्ना द्रमुक जिस तरह धड़ों में बंटी है उससे उसका प्रभाव कम हुआ है। अब अन्ना द्रमुक के महासचिव पलानी स्वामी कुछ शर्तों के साथ बीजेपी से समझौता करने को इच्छुक दिखते हैं।

तमिलनाडु की सियासत में एक बार बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच आपसी संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। दक्षिण राज्यों में अपने विस्तार की संभावना देख रही बीजेपी ने वहां के राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। अन्ना द्रमुक के साथ साथ बीजेपी के संबंध बनते-बिगड़ते रहे हैं। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक में जो बिखराव हुआ, उसमें ही बीजेपी ने अपनी संभावनाएं टटोली। बीजेपी ने राज्य में अन्ना द्रमुक का स्थान लेने का प्रयास किया। बेशक बीजेपी के लिए लोकसभा या विधानसभा में कुछ अच्छे संकेत भी दिखे हैं। लेकिन, बीजेपी और अन्ना द्रमुक दोनों ने आकलन किया कि अभी किसी भी परिस्थिति में अकेले लड़कर द्रमुक को हराना बड़ी चुनौती है। इसलिए एक बार फिर दोनों दलों के गठबंधन की संभावना बनती दिख रही। इसी परिदृश्य में बीजेपी नेता अन्ना मलाई की भूमिका बदलने की संभावना बन गई है।

बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच बनते बिगड़ते संबंधों का पटाक्षेप 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। एआईडीएमके ने बीजेपी के नेता अन्नामलाई की पार्टी पर की गई टिप्पणियों को आधार बनाकर गठबंधन तोड़ा था। साथ ही एआईडीएमके अन्नामलाई की तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्ना दुरई पर की गई टिप्पणी से भी नाराज थी। अन्ना द्रमुक ने एक तरह से भाजपा के अन्ना मलाई के इस्तीफे को मांग को दोनों पार्टियों के बीच समझौते का आधार बना दिया था। दूसरी तरफ अन्नामलाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे थे कि अन्ना द्रमुक से अलग होने का तात्कालिक लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन, आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी संभावना है। बीजेपी एक दिन राज्य में अन्नाद्रमुक का स्थान लेगी। अन्नामलाई ने राज्य में पदयात्रा करके माहौल भी बनाया और बीजेपी की जनसभाओं में भीड़ भी उमड़ी।

बेशक एनडीए को लोकसभा में राज्य से एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन, उत्तरी और पश्चिमी तमिलनाडु में चार पांच सीटों पर उसके प्रत्याशी संघर्ष करते दिखे। विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का मत प्रतिशत भी बढा। यहां दो बातें खासतौर पर आकलन करने लायक है। 2014 या 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के सहयोग पर भी करिश्मा नहीं दिखा पाई। जब अन्ना द्रमुक से अलग होकर 2024 का चुनाव लड़ा तब भी उसका खाता नहीं खुला। जबकि, बीजेपी ने अन्ना द्रमुक से हटकर कुछ दूसरी क्षेत्रीय स्थानीय पार्टियों का गठबंधन बनाया था। इसकी वजह साफ है। बीजेपी को राज्य में प्रचार तो मिला है। लेकिन, अभी उसका जनाधार सिमटा हुआ है। जबकि, द्रमुक अपनी कुछ कमियों के बावजूद अपने संगठन आधार के चलते बार बार सत्ता पाने में कामयाब रही है। निश्चित अन्ना द्रमुक में एम रामचंद्रन और जयललिता जैसे नेताओं के न रहने पर आए बिखराव का फायदा सीधे द्रमुक को मिला है।

इन स्थितियों में अब बीजेपी और अन्ना द्रमुक फिर करीब आने की संभावना बनती दिख रही है। बीजेपी को किसी भी स्तर पर रोकने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने फिर से साठ की दशक की राजनीति को अपनाने की कोशिश की है। वह द्रविड़ अस्मिता पर क्षेत्रीय राजनीति का उभार करना चाहते हैं। त्रिभाषा फार्मूले का विरोध, परिसीमन पर एतराज के साथ साथ सनातन पर रह रहकर आती टिप्पणियों को इसी दायरे में देखा जा सकता है। जहां तक अकेले अन्ना द्रमुक की बात है तो स्टालिन की पार्टी द्रमुक इससे किसी भी तरह भयभीत नहीं है। लेकिन, बीजेपी और अन्ना द्रमुक के साथ आने पर द्रमुक को अपनी रणनीति को और कारगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अन्ना द्रमुक भी द्रविड़ भावना को उभारकर पिछड़ी दलित जातियों को आधार बनाकर खड़ी हुई थी। अन्नादुरई के निधन के तीन साल बाद ही 1975 में एमजी रामचंद्रन ने एआईडीएम के का गठन किया था। इसके दो साल बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बने।

डीएमके हो या एआईडीएमके दोनो ही द्रविड़ पार्टियों में नेताओं की फिल्मी पृष्ठभूमि रही है। जहां तक बीजेपी का इन पार्टियों के साथ आपसी संबंध का है तो बीजेपी के लिए अन्ना द्रमुक ज्यादा सहज और अनुकूल है। हालांकि करुणानिधि के समय द्रमुक से बीजेपी के संबंध कटुता के नहीं रहे। लेकिन, एम के स्टालिन ने बीजेपी के प्रति तेवर तीखे रखे हैं। उनकी पूरी कोशिश रही है कि कि राज्य में बीजेपी को उभरने से रोका जाए। दक्षिण की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने हर स्तर पर प्रयास किया है। तमिल काशी संगमम जैसे आयोजनों को और देश दुनिया के मंचों पर तमिल भाषा की प्रशंसा को इसी दायरे में देखा जा सकता है। यही नहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तमिलनाडु में सक्रियता बनी है। इसका असर भी हुआ है। जिस तमिलनाडु में दूर दूर तक बीजेपी की पहचान नहीं थी। लेकिन बदले समय में बीजेपी का असर कुछ सीमित इलाकों में सही लेकिन दिखता है। खासकर उसका प्रभाव अभी पश्चिम और उत्तरी तमिलनाडु में है। दक्षिण इलाके में उसे पैठ बनानी है।

बीजेपी के लिए दरअसल केंद्र की राजनीति के लिए तमिलनाडु का महत्व है। लोकसभा में तमिलनाडु की 39 सीटें अपना महत्व रखती है। गौरतलब है कि बीजेपी के लिए अभी तमिलनाडु और केरल अभेद दुर्ग बने हुए हैं। ऐसे में दूरगामी सियासत का भले ही अपना अलग महत्व हो लेकिन तमिलनाडु के सियासी परिणाम बीजेपी के लिए हताशा बनते हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के लिए यह रणनीति कारगर दिखती है कि वह अपने राज्य नेतृत्व को अन्ना द्रमुक का साथ लेने के लिए तैयार करे। निश्चित अपने राज नेतृत्व की इच्छा के अनुसार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव अन्ना द्रमुक का साथ छोड़ा। उस समय अन्ना द्रमुक की शर्त अन्नामलाई के इस्तीफे तक ही थी। बीजेपी चाहती है कि मान मनोबल कर समझौते की मेज पर आ सकती थी। लेकिन बीजेपी ने भी अपने राज्य नेतृत्व की भावना के अनुरूप ही एनडीए में अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा।

उधर, अन्ना द्रमुक ने भी इस स्थिति को महसूस किया है कि वह चुनावों में द्रमुक से बुरी तरह मात खा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई थेनी सीट भी उसने इस बार गवांई। थेनी सीट भी उसने तब जीती थी जब उसका बीजेपी के साथ गठबंधन था। अन्ना द्रमुक के मत प्रतिशत पर भी असर पड़ा और संगठन भी काफी हद तक कमजोर हुआ है। इन स्थितियों में अन्नाद्रमुक बीजेपी के साथ ज्यादा शर्त बांधने की स्थिति में नहीं है। द्रमुक नेता पलानीस्वामी यही चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन की स्थिति में उसके बागियों से समझौता नहीं हो। यानी पनीरसेल्वम और दिनाकरन को शामियाने से दूर रखा जाए। बीजेपी के लिए अपने अन्नामलाई जैसे नेताओं को आश्वस्त करना मुश्किल काम नहीं। इसी रणनीति में अन्ना मलाई को नई जिम्मेदारी देने की रणनीति पर विचार हुआ है। निश्चित अन्ना मलाई और पनीरसेल्वम एक ही इलाके के हैं और एक ही गोड जाति के हैं। इसलिए उन्हें क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने की होड़ भी रहती है।

बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु सहित दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटों पर दूसरे राज्यों की तुलना में अनुपातिक तौर पर कमी नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि तमिलनाडु में भी सीटों को लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। बीजेपी को मंथन करना होगा कि अन्ना द्रमुक के साथ तालमेल में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को किस तरह समायोजित किया जा सकता है। खासकर तब जबकि उसमें द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों से निकले हुए नेताओं का शुमार है। जातियों के अपने समीकरण है। पीएमके मजबूत वनियार जाति से आते हैं। निश्चित जातीय समीकरणों का ताना बाना अपना महत्व रखता है। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 39 में 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली बीजेपी की नजर दरअसल 2026 के विधानसभा चुनाव पर भी रही। पार्टी चुनाव के परिणाम से ही अपना आकलन करना चाहती थी। पीएमके तमिल मनीला कांग्रेस और ए एमएम के जैसे नौ दलों का साथ लेकर तमिलनाडु के परिणामों ने ही बीजेपी को महसूस कराया है कि तमिलनाडु से वांछित परिणामों के लिए कुछ और बड़े गलियारों को पार करना होगा। उसका ओबीसी कार्ड और तीसरी शक्ति बनने का प्रयोग कामयाब नहीं रहा। उधर लोकसभा चुनाव से पहले एक्स पर थैंक्यू अब मत आना लिखने वाली अन्ना द्रमुक संकेत दे रहे हैं कि वेलकम फिर वापस आओ।

प्रो. डॉ. भावना ढींगरा ने 13वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया अपना शोध

भोपाल। एम्स भोपाल की प्रो. डॉ. भावना ढींगरा ने लक्ज़मबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नियोनेटल स्क्रीनिंग के 13वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया अपना शोध एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के कुशल नेतृत्व में, संस्थान वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी प्रतिबद्धता के तहत, एम्स भोपाल की शिशु रोग विभाग की प्रोफेसर, प्रो. (डॉ.) भावना ढींगरा ने लक्ज़मबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नियोनेटल स्क्रीनिंग के 13वें सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने नवजात शिशुओं में सामान्य चयापचय संबंधी विकारों और हीमोग्लोबिनोपैथी की स्क्रीनिंग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और उनके कार्य को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अत्यधिक सराहा गया। विकसित देशों में नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिससे जन्मजात और चयापचय संबंधी विकारों की शीघ्र पहचान और उपचार संभव हो पाता है। हालांकि, भारत में अब तक सार्वभौमिक नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है। एम्स भोपाल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य भारत की पहली नवजात स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की है। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने इस उपलब्धि की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, नवजात स्क्रीनिंग एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, जो जन्मजात विकारों के शीघ्र निदान और उपचार द्वारा नवजात शिशुओं का जीवन बचा सकती है। एम्स भोपाल नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने और शिशु रोग चिकित्सा में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. भावना ढींगरा का वैश्विक मंच पर योगदान हमारे संस्थान की चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

बैतूल जिले में अलग-अलग तिथियों में होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन

बैतूल। जिले के नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों में अलग-अलग तिथियों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नगरी निकायों तथा जनपद पंचायतों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत आमला एवं नगर पालिका आमला में 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत मुलताई एवं नगर पालिका मुलताई में भी 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा। जनपद पंचायत भीमपुर में 30 अप्रैल को, जनपद पंचायत बैतूल, नगर पालिका बैतूल एवं नगर परिषद बैतूल बाजार में 2 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा। जनपद पंचायत भैंसदेही एवं नगर परिषद भैंसदेही तथा जनपद पंचायत प्रभात पट्टन में 5 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा। जनपद पंचायत शाहपुर एवं नगर परिषद शाहपुर में 8 मई को, जनपद पंचायत चिचोली एवं नगर पालिका चिचोली में 16 मई को तथा जनपद पंचायत आठनेर, नगर परिषद आठनेर में 16 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा। इसके अलावा जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी एवं नगर परिषद घोड़ाडोंगरी, नगर पालिका सारनी में 22 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन होगा।

ग्राम कोल्हिया में पांच दिवसीय कोया पुनेम गाथा का शुभारंभ

बैतूल। युवा आदिवासी विकास संगठन कोल्हिया द्वारा ग्राम में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा एवं रैली निकालकर पड़ापेन स्थापना के 9वीं वर्षगांठ पर कोया पुनेम गाथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में रैली में उपस्थित रहे और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजक मनोहर कोराची और राजेश वरकड़े ने बताया कि इस विशेष आयोजन में छिंदवाड़ा के गोंडी धर्माचार्य विलास कुमरे द्वारा कोया पुनेम का वाचन किया जा रहा है। कोया पुनेम गाथा गोंड समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को उजागर करती है, जो समुदाय की पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने में सहायक होती है। महाजन गेंदु वरकड़े ने बताया कि इस पांच दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलंकार ग्रुप आमला के संचालक कैलाश सलामे, बैतूल की सुपरहिट गायिका ममता उइके और सुपरहिट सिंगर शिवम इरपाचे अपने लाइव गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा, पारंपरिक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति होगी, जिसमें गोंडी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ग्राम कोल्हिया में हो रहे इस आयोजन से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बल मिलेगा। स्थानीय ग्रामीणों और आयोजकों ने इस पहल को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोया पुनेम का महत्व- कोया पुनेम गोंड समाज की धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें प्रकृति पूजा, सामाजिक नियम और समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख है। यह गाथा समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करती है। यह आयोजन गोंड समाज के लोगों के लिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी प्रेरणादायक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। ग्राम कोल्हिया में पांच दिवसीय आयोजन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे गांव को सजाया गया है और लोग बड़ी श्रद्धा एवं उमंग के साथ आयोजन में शामिल हो रहे हैं।

दुर्गंध दूर करने नगरपालिका नहीं उठा रही कोई कदम, लोगों में बढ़ रही नाराजगी

कचरे की प्रोसेसिंग के दौरान उठ रही तेज दुर्गंध

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान है। यहां सालों तक कचरा जमा किया गया था, जिसकी अब प्रोसेसिंग की जा रही है। इसका ठेका नोएडा की एजेंसी को दिया गया है, जो 1 लाख 33 हजार टन कचरा नष्ट करने के लिए 300-300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दो प्लांट लगाकर कचरे की प्रोसेसिंग कर रही है। लेकिन जमीन में वर्षों से दबे कचरे के निकलते ही इसके साथ तेज दुर्गंध भी उठ रही है। जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। हालात यह है कि यहां रहने वाले लोगों को दुर्गंध से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर रहना पड़ता है। रात में सोना तक मुश्किल हो रहा है। बता दे कि नगरपालिका शहर के 33 वार्डो से निकलने वाले कचरे को गौठाना ट्रेंचिंग ग्राउंड में एकत्रित करती है। वर्षो से यहां कचरा जमा किये जाने से कचरे का पहाड़ लग गया है। लंबे समय से कचरा इकठ्ठा होने और सडने़ की वजह से तेज दुर्गंध उठ रही है। गंदगी व कचरे के कारण रहवासी घर के दरवाजे लगा कर रखते हैं। अब तो खाना भी मुंह ढांककर खाना पड़ रहा है, लेकिन नगरपालिका द्वारा कचरे से उठने वाली दुर्गंध को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास तक नहीं किये जा रहे है। जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है।

प्रतिदिन निकलता है सैकड़ों टन कचरा- नगरपालिका द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहित किया जाता है। एक अनुमान से शहर के 33 वार्डो से लगभग प्रतिदिन 30 से 40 टन कचरा निकल जाता है और इस कचरे को शहर के समीप स्थित गौठाना के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा किया जाता है। पहले आसपास ज्यादा मकान नहीं थे, लेकिन अब आबादी बढने़ के साथ-साथ मकानों का भी निर्माण हो गया है। ऐसे में हवा चलने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा उडकर घरों तक पहुंच जाता है और लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। रहवासी बताते है कि कचरे की दुर्गंध के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी आती है। कचरे के कारण मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है।

किसी भी केमिकल का छिडक़ाव नहीं कर रही नपा- नगरपालिका पूरे शहर में बदबू को दूर करने के लिए कचरे और यहां तक की नालियों में भी बीएचसी यानी गैमेक्जेन का पाउडर समेत अन्य छिडक़ाव करती है। लेकिन यहां पर चूंकी यह ठेका नोएडा की ईकोस्टन कंपनी को दिया है। 5 करोड़ रुपए का यह ठेका है, इसलिए नपा यहां पर किसी तरह का छिडक़ाव नहीं कर रही है। जबकि यहां पर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन डाल दी जाए तो यह बदबू दूर हो जाएगी। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि रोजाना लगभग 40 टन कचरा यहां पर शहर से निकालकर डाला जाता है। इस तरह इतनी बड़ी मात्रा में दबा हुआ कचरा निकलने से इसके साथ गैसे भी निकल रही है। रोजाना 600 टन कचरा यहां प्रोसेस हो रहा है, जमीन में से कचरा निकालकर नष्ट किया जा रहा है।

ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगा है कचरे का पहाड़- शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लाखों टन कचरा जमा हो गया है। यहां अभी भी शहर का कचरा एकत्रित किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्ट करने के बाद इसे, इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। जिससे यहां कचरे की मात्रा बढ़ते ही जा रही है। लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी नगरपालिका की लापरवाही साफ झलक रही है। लापरवाही यह भी है कि कचरे की प्रोसेसिंग के दौरान कचरे से दुर्गंध या हानिकारक गैस न निकले, इसके लिए नपा द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये है। इस इलाके में हर तरफ कचरा ही नजर आता है। कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं।

इनका कहना है

कचरा कई सालों से दबा हुआ था, इसे निकालने के कारण दुर्गंध फैल रही है। कचरे से दुर्गंध न आये, इसके लिए केमिकल का छिडक़ाव किया जा रहा है, लेकिन केमिकल भी एक निश्चित मात्रा में ही डाला जा सकता है। यदि लोगों को आपत्ति है तो हम कुछ दिनों के लिए काम रोक भी सकते है, लेकिन बारिश की वजह से कचरा गीला होगा और फिर तेज दुर्गंध उठेगी। हमारा प्रयास है कि यह कार्य जल्दी खत्म हो जाये।

- नीरज धुर्वे, एई, नगरपालिका बैतूल।

विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने आत्मविश्वास के साथ करें कर्म : प्रभारी मंत्री

बैतूल। पीएमश्री महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को स्कूल चले हम अभियान के तहत भविष्य से भेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, जिला पंचायत सीईओ

अक्षत जैन, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.अनिल सिंह कुशवाह मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर उन्हें पाठ्य पुस्तकें भेंट की। कार्यक्रम के पूर्व प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने नीट और जेईई के बच्चों से चर्चा की और उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, गृहत्यागी ये आदर्श विद्यार्थी के पांच लक्षण हैं। उन्होंने ये गुण धारण कर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि हम जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे पाने के लिए एकाग्रचित होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कर्म करें। आप निश्चित ही सफल होंगें।

छात्राओं को नगद राशि देने की घोषणा- कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाषण और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को 500-500 रुपए की नगद राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कक्षा दसवीं में 85 प्रतिशत लाकर लैपटॉप और स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्रा सृष्टि साहू को भी सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल से विद्यार्थियों ने हंसी-ठहाकों के बीच कैरियर निर्माण के गुण सीखे। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए समाज की सेवा, राष्ट को सशक्त बनाने और विश्व के कल्याण के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया।

विद्यार्थी अपने माता-पिता की बातों का पालन करें- प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिन विद्यार्थियों में अपने शिक्षक, आचार्य को ध्यान पूर्वक सुनने की प्रवर्ति रहती है, वे विद्यार्थी अपने माता-पिता की बातों का पालन करते हैं। ऐसे विद्यार्थी ही जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़े शुभ चिंतक माता-पिता होते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अपने-अपने माता-पिता की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने और उनकी आज्ञा का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने हमारे जीवन में गुरु के महत्व से भी विद्यार्थियों को अवगत कराया और गुरुजनों का सम्मान करने के लिए कहा।

विद्यार्थी अपना भाग्य जमाने के लिए करें कर्म- प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपना लक्ष्य तो तय कर सकते हो, लेकिन भाग्य को नहीं बदल सकते। भाग्य आपको जहां ले जाना है वहां लेकर जाएगा, लेकिन भाग्य भी आपको वहीं लेकर जाएगा जिस दिशा में आपके कर्म होंगे। जिस तरह शेर को अपना शिकार करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों को अपना भाग्य जमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। जिस भी दिशा में आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस दिशा में आप सतत प्रयास करते रहे। निश्चित ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

मुख्यमंत्री ने समरकूल के डायरेक्टर आशुतोष गुप्ता व तनुज गुप्ता को किया सम्मानित

बैतूल। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में समरकूल ग्रुप के डायरेक्टर आशुतोष गुप्ता व तनुज गुप्ता को एयर कूलर के उत्पादन क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवॉर्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में देश की कई बड़ी कंपनियों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार मध्यप्रदेश

में नये उधोग लगाने के लिए सभी को आह्वान करती है, क्योंकि मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार के द्वारा उद्योग जगत के लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ-साथ उनकी सभी जरूरतों का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा ही किया जा रहा है। समरकूल बैतूल के डिस्टीब्यूटर हर्ष शाह एवं चिचोली के डीलर विनय आर्य ने बताया कि देश और मध्यप्रदेश में समरकूल ग्रुप विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं।

शहर और जिले में अभी से गहराने लगा जल संकट

देवास/मोहन वर्मा। मार्च बीतते बीतते शहर और जिले में अभी से पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है । जिले के अलग अलग हिस्सों से पानी की किल्लत के समाचार आने लगे है । शहर के अनेक वार्डों में भी दो दिन छोड़कर पानी दिए जाने को लेकर आज कांग्रेस पार्षदों ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल पवार के नेतृत्व में नगर निगम में मटकेफोड़कर प्रदर्शन किया । शहर में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। शहर के वार्डों में नियमित रुप से जलप्रदाय नहीं हो पा रहा है। कई वार्डों में पिछले तीन दिनों से जलप्रदाय नहीं हुआ। पानी की समस्या को लेकर आज कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में मटके फोडक़र विरोध किया। पार्षदों का कहना है कि इस समस्या से शहर के 45 वार्डों की जनता परेशान है, नगर निगम अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। वहीं महापौर प्रतिनिधि का कहना है कि गर्मी के पूर्व ही शिप्रा नदी का वाटर लेवल कम हुआ है। उन्होनें कहा कि निश्चित रुप से पानी की समस्या है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ऐसी परिस्थिति में राजननीतिक नौटंकी नहीं करके समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास व सहयोग करना चाहिए। शहर के लगभग सभी वार्डों में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। जबकि अभी गर्मी ने अपने तेवर बताए नहीं उससे पहले नगर निगम के जलप्रदाय विभाग के अधिकारियों ने अपने तेवर बताना शुरु कर दिए। इस समस्या से परेशान लोगों का कहना है कि हम समय पर जलकर का भुगतान करते हैं, उसके बावजूद नियमित रुप से जलप्रदाय नहीं होना निगम की घोर लापरवाही औरअधिकारियों का भ्रष्टाचार है। रहवासियों ने बताया कि नगर निगम की जल वितरण प्रणाली बहुत खराब है। लोगों को पानी के लिए सुबह 4 बजे से जागना पड़ता है। उसके बाद भी पीने का पानी गंदा आता है। नेता प्रतिपक्ष पार्षद प्रतिनिधि राहुल पंवार ने बताया कि यदा-कदा पानी आता है तो गंदा और मटमेला पानी आता है, इसकी शिकायत महापौर और निगम आयुक्त को कर चुके हैं। शहर के सभी 45 वार्डों में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। नगर निगम इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

बैतूल में मंत्री के पैरों पर गिरा पिता

दामाद ने बेटी को तीन तलाक देकर छोड़ा, डॉक्टर पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप

बैतूल (नप्र)। बैतूल के प्रभारी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गुरुवार को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसी दौरान एक शख्स रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की गुहार लगाने लगा। उसने बताया कि दामाद ने उसकी बेटी को तीन तलाक देकर छोड़ दिया। मंत्री ने शख्स को उठाकर गले लगाया और तुरंत बैतूल एसपी और कलेक्टर से बात की। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

ससुराल वालों ने छत से धक्का दिया- कंपनी गार्डन क्षेत्र के रहने वाले सिकंदर खान की बेटी के साथ उसके ससुरालवालों ने दहेज के लिए क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने पहले उसे जहर पिलाया और फिर छत से फेंक दिया। इस हादसे में युवती स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई।

तीन तलाक देकर छोड़ने का आरोप- सिकंदर ने बताया कि इस घटना के बाद उसके पति ने उसे सड़क पर ही तीन तलाक दे दिया। उन्होंने बेटी के इलाज के लिए अपनी गाड़ी और घर तक बेच दिया, लेकिन न्याय की आस में वे दर-दर भटकते रहे। तीन महीने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक आरोपी पति और ससुराल पक्ष पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।

डॉक्टर पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप- पीड़िता ने मंत्री से उस डॉक्टर की भी शिकायत की, जिसके अस्पताल में उसे जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता के अनुसार, 19 नवंबर 2024 को ससुरालवालों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि गर्भस्थ शिशु सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच करनी होगी। इसके बाद उसे तीन गोलियां खाने को दी गईं, ड्रिप चढ़ाई गई और एक विशेष इंजेक्शन लगाया गया। रात 9 बजे उसे असहनीय दर्द शुरू हुआ और 20 अप्रैल 2024 की सुबह 4 बजे उसका गर्भपात हो गया।

मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया- जब मंत्री पटेल को इस मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों से चर्चा कर इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।

जबलपुर कलेक्टर जैसा एक्शन दूसरे जिलों में क्यों नहीं

कांग्रेस ने स्कूल संचालकों की लूट से अभिभावकों को बचाने सीएस को लिखी चिट्ठी

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेशभर में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर अंकुश न लगा पाने को लेकर मुख्य सचिव को पीले चावल के साथ पत्र लिखा है। त्रिपाठी ने कहा है कि स्कूल संचालकों द्वारा महंगी किताबें व ड्रेस कमीशन देने वाली दुकान से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इनके द्वारा फीस भी मनमानी बढ़ाई गई है जिनके खिलाफ कार्यवाही सरकार को करना चाहिए।

त्रिपाठी ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अनुचित शुल्क वसूली, महंगी निजी प्रकाशकों की किताबों की अनिवार्यता तथा आरटीई नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर समस्याओं को कांग्रेस द्वारा समय-समय पर उजागर किया गया पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है जिससे ऐसी लूट को रोका जा सके। विवेक ने कहा कि हाल ही में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा निजी स्कूलों पर की गई कार्रवाई से शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगा है।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में होनी चाहिए ताकि अन्य जिलों में निजी स्कूलों की मनमानी रोकी जा सके और छात्रों व अभिभावकों को राहत मिले। निजी स्कूलों के खिलाफ दर्ज सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का 15 कार्य दिवस में निराकरण कर उचित कार्यवाही करें। त्रिपाठी ने मुख्य सचिव को इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है। इसमें ये मुद्दे प्रमुख रूप से सीएस के ध्यान में लाए गए हैं। एनसीईआरटी की किताबों को 1 फर्स्ट क्लास से ही अनिवार्य किया जाए, वहीं नर्सरी, केजी-1, केजी 2 की किताबों में 5 वर्ष तक किसी भी बदलाव पर अंकुश लगाया जाए ताकि अभिभावकों पर महंगी किताबों का आर्थिक बोझ न पड़े। स्कूलों द्वारा चुनिंदा दुकानों से खरीददारी कराने पर रोक लगे और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर किताबों की सूची तत्काल डाली जाएं। नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, 10 प्रतिशत का नियम कड़ाई से लागू हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिया जाए और इसके पालन की निगरानी हो। इसके लिए जिला और प्रदेश स्तर पर उचित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनें। हर जिले में कलेक्टर कार्यालय में एक विशेष दिन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की जनसुनवाई की जाए।

एमपी की 15008 वक्फ संपत्ति से सिर्फ दो करोड़ आय

बोर्ड अध्यक्ष बोले- सौ करोड़ सालाना आना चाहिए, भोपाल के नईम समेत कई पर निकली रिकवरी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने कहा कि एमपी वक्फ बोर्ड के अधीन 15008 संपत्तियां दर्ज हैं। इन संपत्तियों से कम से कम सौ करोड़ रुपए सालाना आय होना चाहिए लेकिन दो करोड़ रुपया भी नहीं आ पाता है। इसलिए जन कल्याण के काम में खर्च नहीं हो पाता। अब नए बिल के लागू होने के बाद राशि आएगी तो जनकल्याण के लिए खर्च की जा सकेगी। भोपाल में नईम खान ने वक्फ की प्रापर्टी का अवैध उपयोग किया है, उनके विरुद्ध आरआरसी जारी हुई है।

गुरुवार को बीजेपी दफ्तर में मीडिया से चर्चा करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पटेल ने कहा कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई जगहों पर शिकायतें हुईं। जिसमें न्यायालय के साथ सरकार के दफ्तर भी शामिल हैं। वक्फ बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने धमकाने, डराने का काम किया। जेपीसी ने देश भर में घूमकर सुझाव मांगे। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव मांगे। दो करोड़ से अधिक लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं। देश के भाईचारे और समाज व देश हित में वक्फ बिल लाया गया है। असल हकदार जरूरत मंद मुसलमानों के लिए यह बिल है। चंद ताकतवर, धनाढ्य मुसलमान लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, वे इसका विरोध कर रहे हैं। अब असली जरूरत मंद मुसलमानों के हित में इन संपत्तियों से होने वाली आय को खर्च किया जा सकेगा।

विपक्ष पांच नाम बताए जिन्हें सीएए के कारण देश से निकाला गया- पटेल ने कहा कि विपक्ष के लोग आज भी पांच नाम या एक नाम बता पाने की स्थिति में नहीं हैं कि सीएए के बाद किसी को देश से निकाला गया है। जेपीसी के बाद 15 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई थी और कलेक्टरों को फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड ने 15 में से 12 बिंदुओं पर जानकारी भेज दी है। अब एमपी के लिए एक नया पोर्टल वामसी नाम से बनाया जा रहा है। शेष तीन बिन्दु राजस्व विभाग से संबंधित हैं जिसमें राजस्व रिकार्ड में संपत्तियों की क्या स्थिति है? निजी है या सरकारी है। बंदोबस्त के पहले जमीन का खसरा नम्बर क्या था? इसकी जानकारी कलेक्टरों से मांगी गई है।

कांग्रेस नेताओं का वक्फ पर कब्जा, इसलिए कर रहे विरोध- वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेता रियाज खान 7.11 करोड़ की आरआरसी जारी हुई है। इन्होंने वक्फ में 15 दुकानें बताई थी, इसकी जांच हुई तो 115 दुकानें मिलीं। ऐसे ही 1.84 करोड़ की रिकवरी सागर जिले के बीना में कांग्रेस नेता इकबाल खान पर निकली है। नईम खान भोपाल के हैं, उनके विरुद्ध भी सवा करोड़ रुपए आरआरसी जारी हुई है। ये वक्फ की आमदनी से अपना पेट भर रहे हैं। इस बिल से उन्हीं लोगों का विरोध सामने आ रहा है। वास्तव में जरूरतमंद मुसलमान तो इस बिल से खुश है।

डिसेंट क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी अथर्व राठौर ने किया धार का नाम रोशन

धार। डिसेंट क्रिकेट अकादमी के अथर्व राठौर ने दिसम्बर और जनवरी में मुरैना की डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरुप उन्हें चंबल संभाग की टीम में स्थान मिला है। अंतर संभागीय प्रतियोगिता में वो भाग लेंगे जिसमें उनका मैच 4 अप्रैल को भोपाल संभाग के विरुद्ध खेला जाएगा।

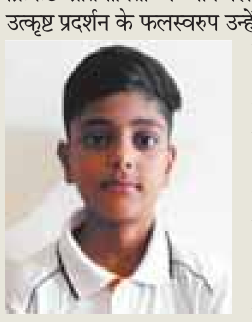

डिसेंट क्रिकेट अकादमी में अथर्व 7 वर्ष की उम्र से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। उनके चयन से अकादमी के कोच आशीष वसुनिया, अध्यक्ष सचिन बाफना, सचिव अरुण यादव, उपाध्यक्ष कपिल यादव, संरक्षक अंबालाल पाटीदार, सदस्य अजय योगी, केतन कुचेकर, प्रतीक निगम, यूनुस शेख, नीलेश चौधरी आदि में खुशी का माहौल है। अकादमी की ओर से अथर्व को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी व ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ने और भविष्य में देश - प्रदेश की टीम में चयनित होने की कामना की है ।

टीकमगढ़–सागर हाईवे पर टक्कर के बाद एक बस खाई में पलटी, 10 मजदूर घायल

टीकमगढ़ (नप्र)। ग्वालियर से सागर जा रही बस पलटने से उसमें बैठे 10 मजदूर घायल हो गए। दो की हालात गंभीर होने पर टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे बड़ागांव के नजदीक टीकमगढ़ सागर राजमार्ग मार्ग पर कृषि उपज मंडी के पास हुई है।हादसा उसी रूट पर इंदौर से सागर जा रही बस से टकराने के कारण हुआ, जिससे बस खंती में जाकर पलट गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया।

मक्सी बायपास पर चलती कार बनी आग का गोला, दंपत्ति की बाल–बाल बची जान

मक्सी (नप्र)। मक्सी बायपास पर गुरुवार दोपहर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। कार में सवार कैलाश झाला और किरण झाला इस हादसे में बाल-बाल बच गए। समय रहते वे दोनों कार से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन उनकी कार धू-धू कर जल गई।

कैसे हुआ हादसा?- जानकारी के अनुसार कैलाश झाला किरण झाला के साथ मक्सी में अपने साडू से मिलने आ रहे थे। वे सतनाम ढाबे के पास पहुंचे, तो कार के अंदर से धुआं उठता हुआ नजर आया। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर स्थिति का जायजा लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तत्काल कार से उतरने का फैसला किया। दोनों कार से बाहर निकले ही थे कि अचानक उसमें आग की लपटें उठने लगीं। देखते-देखते पूरी कार आग के गोले में बदल गई।

दमकल ने पाया आग पर काबू- घटना के दौरान वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों व स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी के बस में नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाजापुर और तराना से दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

शॉर्ट सर्किट बना आग की वजह- प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि, मामले की विस्तृत जांच तराना पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र तराना थाना अंतर्गत आता है।

उमा भारती ने महाकाल मंदिर में किए दर्शन

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने दर्शन किए। उन्होंने गर्भ गृह में जाकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। पूजन ओम पुजारी द्वारा कराया गया। उमा भारती ने गर्भ गृह में करीब 20 मिनट तक पूजन किया। इसके बाद वे नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर खंडवा को नीति आयोग से मिला 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में किया उल्लेखनीय सुधार

भोपाल (नप्र)। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत खंडवा ज़िले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। नीति आयोग ने जिले के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की है। नीति आयोग ने प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिये खंडवा ज़िले को 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिये ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाने के प्रयास प्रमुख रहे हैं।

खंडवा की यह उपलब्धि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय: उप मुख्यमंत्री शुक्ल- उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खंडवा की यह उपलब्धि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत इस तरह की सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि खंडवा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, मैदानी कार्यकर्ताओं की सराहना की है।

फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर कार्यक्षमता में की गई वृद्धि- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये योजनाबद्ध प्रयास किए गए। जिले में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। आउटरीच स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई। इसके साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की गई।

हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान कर संस्थागत सुरक्षित प्रसव किया गया सुनिश्चित

ज़िले में मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिये गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रसव केंद्र स्थापित किए गए। चिन्हित उप-स्वास्थ्य केंद्रों को प्रसव सुविधा से सुसज्जित किया गया, जिससे घर पर प्रसव के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया। 'लक्ष्य' एवं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएएस) के तहत ज़िले की 25 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत किया गया, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण और कुपोषित बच्चों की विशेष देखरेख

ज़िले में शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए समेकित प्रयास किए गये। सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ कुपोषण निदान की सघन कार्यवाही से सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारम्भ हुए। 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाया गया। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पूरक पोषण योजनाओं से जोड़ा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशु पोषण और देखभाल पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को किया सशक्त

जिले में 177 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के रूप में क्रियाशील किया गया, जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुईं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लक्ष्य से अधिक मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचारित किया गया। नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज़ (एनसीडी) कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया गया, जिससे मरीजों का समय पर उपचार संभव हुआ।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में पुरस्कार राशि से किए जायेंगे विकास कार्य

कलेक्टर खंडवा श्री ऋषभ गुप्ता ने कहा कि नीति आयोग द्वारा प्राप्त 3 करोड़ रुपए की राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के चिन्हित क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जिससे ज़िले के विकास को और गति मिलेगी।

सीएम का दतिया दौरा आज

मां बगलामुखी की करेंगे पूजा,पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया तैयारियों का जायजा

दतिया (नप्र)। सीएम डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को दतिया में पीतांबरा पीठ पहुंचेंगे। चैत्र नवरात्र के छठवें दिन सीएम मां बगुलामुखी की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। गुरुवार को पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और एसपी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ स्टेडियम ग्राउंड, एयरपोर्ट और मां पीतांबरा पीठ मंदिर का निरीक्षण किया।

एयरपोर्ट से पीतांबरा पीठ तक मॉकड्रिल

शुक्रवार को मुख्यमंत्री के पीतांबरा पीठ पहुंचने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को एयरपोर्ट से मंदिर तक की सड़कों की सफाई की गई है। स्थानीय समाज सेवी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत की तैयारियां कर ली हैं। पुलिस ने एयरपोर्ट से पीतांबरा पीठ तक के मार्ग पर पुलिस वाहन, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों से मॉकड्रिल की । पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सीएम का दतिया पहुंचने का शेड्यूल

दोपहर 12.40 बजे भोपाल से दतिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री करेंगे पीताम्बरा पीठ के दर्शन।

दोपहर 13.10 मिनट पर अशोकनगर एयरपोर्ट से चंदेरी के लिए रवाना होंगे।

माधव टाइगर रिजर्व में एक और टाइगर को छोड़ा गया

पिंजरे से निकलते ही जंगल की तरफ दौड़ा ; केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शेयर किया वीडियो

भोपाल (नप्र)। वन विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार शिवपुरी स्थित देश के 58वें और मध्यप्रदेश के 9वें माधव टाइगर रिज़र्व में उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व से लाए गए एक और नर बाघ को छोड़ा। लगभग बीस दिन पहले यहां एक मादा बाघिन को छोड़ा गया था। अब माधव टाइगर रिज़र्व में कुल 6 बाघ (4 वयस्क और 2 शावक) मौजूद हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि, यह कदम वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे क्षेत्रीय पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

एक महीने में पूरा हुआ वादा- 10 मार्च 2025 को माधव राष्ट्रीय उद्यान को माधव टाइगर रिज़र्व का दर्जा मिला था, जहां एक बाघिन को छोड़ा गया था। उस समय कहा गया था कि जल्द ही एक और बाघ लाया जाएगा। इसके एक महीने के भीतर ही बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व से एक और नर बाघ को शिवपुरी लाकर सुरक्षित छोड़ा गया।

इसके बाद माधव टाइगर रिज़र्व में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। वन अधिकारियों की देखरेख में बाघ को छोड़ने के बाद उसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चार सालों से शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के पुनर्वास और इसे राष्ट्रीय टाइगर रिज़र्व का दर्जा दिलाने के प्रयास में लगे हुए थे। पहले, 2023 में, वे यहां तीन बाघ लेकर आए थे। इसके बाद, 10 मार्च 2025 को अपने पिता माधवराव सिंधिया की जयंती पर एक और बाघिन को यहां लाया गया, और इसी दिन इसे टाइगर रिज़र्व का दर्जा मिला।

सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- नए मेहमान का माधव टाइगर रिज़र्व में स्वागत है। आज सुबह शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिज़र्व में बांधवगढ़ से लाए गए बाघ का सफल पुनर्स्थापन किया गया। रिज़र्व में बाघों की निरंतर बढ़ती संख्या से न केवल मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र समृद्ध होगा, बल्कि शिवपुरी के विकास को भी नई गति मिलेगी।

आरकेएमपी से सहरसा के बीच चलेगी 13 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेन

बिहार व उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

भोपाल (नप्र)। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। जिसमें गाड़ी संख्या 01663/01664 रानी कमलापति-सहरसा-रानी कमलापति ग्रीष्मकालीन विशेष साप्ताहिक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के नर्मदापुरम एवं इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस/139 के माध्यम से ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

ट्रेन नंबर 01663: रानी कमलापति - सहरसा (प्रत्येक सोमवार, 13 ट्रिप)- गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति - सहरसा ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन शाम 4:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और रास्ते में शाम 5:40 बजे नर्मदापुरम, शाम 6:15 बजे इटारसी एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 3:15 बजे सहरसा पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 01664- सहरसा - रानी कमलापति (प्रत्येक मंगलवार, 13 ट्रिप)- गाड़ी संख्या 01664 सहरसा - रानी कमलापति ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 08 अप्रैल 2025 से 01 जुलाई 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन शाम 6:30 बजे सहरसा स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 6:35 बजे इटारसी, शाम 7:20 बजे नर्मदापुरम पहुंचेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित ठहराव के बाद अगले दिन रात 9:10 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव- रास्ते में यह गाड़ी रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर जं., बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं. एवं मानसी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

नरेंद्र मोदी विचार मंच के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश निगम व जिला महामंत्री प्रवीण टांक का व्यापारी महासंघ ने किया स्वागत

धार। व्यापारी महासंघ (सेमी होलसेल एवं खेरची) द्वारा नरेंद्र मोदी विचार मंच की मुख्य शाखा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश निगम व नवनियुक्त जिला महामंत्री प्रवीण टांक का व्यापारी महासंघ द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया। नवनियुक्त पदाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने एवं संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी गौरव जैन ने बताया कि इस अवसर पर महासंघ के संरक्षक पवन जैन गंगवाल, व्यापारी महासंघ सचिव पारस जैन गंगवाल, प्रकाश सोलंकी कमल हारोड़, शांतिलाल शर्मा, राकेश राठौड़ प्रकाश राठौड़, भय्युराम, राजेश राठौर आदि व्यापारीगण उपस्थित थे । आभार सचिव पारस जैन ने माना।

बदनावर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन की तैयारियों का कलेक्टर, एसपी ने लिया जायजा

धार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बदनावर के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल उज्जैन-बदनावर हाईवे पर खेड़ा आइलैंड का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। कार्यक्रम 7 अप्रैल को होना प्रस्तावित है।

बदनावर कृषि उपज मंडी का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण- कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज बदनावर कृषि उपज मंडी का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में संचालन व्यवस्था, भोजन प्रबंधन और साफ-सफाई को लेकर पड़ताल की। कलेक्टर ने मंडी प्रशासन को व्यवस्थाएं और अधिक बेहतर एवं सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान एसपी मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

॥ मंदिरम् ॥ 74

क्रिमची मन्दिर, जम्मू-कश्मीर

क्रिमची मन्दिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर ज़िले के क्रिमची गाँव में स्थित सात प्राचीन हिन्दू मन्दिरों का एक परिसर है। यह उधमपुर नगर से लगभग 12 किमी दूर बीरुनाला नामक जलधारा के किनारे स्थित हैं। स्थानीय लोग इन्हें पाण्डव मन्दिर भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इन मन्दिरों का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। मन्दिर संख्या 6 और 7 को कई शताब्दियों पहले हानि पहुँची थी। स्थानीय मान्यता इन मन्दिरों को महाभारत के पाण्डव भाईयों से जोड़ती है कि वे यहाँ लम्बे समय के लिए रुके थे। यह माना जाता है कि स्थानीय राजा कीचक ने क्रिमची नगर और राज्य की स्थापना किया थी।

भोपाल शहर सरकार का बजट पेश

संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की वृद्धि, पानी भी महंगा, 3611 करोड़ से अधिक का बजट पेश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की भोपाल की शहर सरकार का बजट पेश हो गया है। महापौर मालती राय ने 3611 करोड़ 79 लाख 75 हजार रुपये का बजट प्रस्तुत किया। भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इससे भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

गुरुवार को भोपाल नगर निगम का बजट पेश हुआ। मेयर मालती राय ने 3611 करोड़ 79 लाख 75 हजार रुपये का बजट पेश किया। इस बार भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं उपभोक्ता प्रभार जल, सीवेज, ठोस अपशिष्ट में भी 15 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव है। टैक्स बढ़ाने से शहर में 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपये

भोपाल के वार्डों के विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपए का प्रावधान है। बजट में पहली बार जोन अध्यक्षों के लिए विकास राशि का आवंटन किया गया है। हर जोन को 10 लाख रुपये दिए गए हैं। दीनदयाल परिसर लाल घाटी चौराहे पर 7 करोड़ से नमो वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 400 करोड़ रुपये पीएम आवास के लिए निर्धारित किए हैं। भोपाल के मुख्य मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वार बनेगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

यह मिली सौगात

- गीता भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़
- अमृत-2 योजना के लिए 75.46 करोड़
- अमृत-2 व्यवसायिक प्रसारों के निर्माण के लिए 60
- विसर्जन घाटों के निर्माण के लिए 30.2 करोड़
- जीआईएस के तहत शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए 10 करोड़
- मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़
- पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़
- नगर निगम के कर्मचारियों के बच्चों को 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने पर 10 हजार रुपये प्रति छात्र देने का प्रस्ताव है।

नल नालियों के निर्माण के लिए 20000 लाख का बजट

इसके अलावा जल भराव से निपटने के लिए, पानी की निकासी और नाला नालियों के संधारण और निर्माण के लिए 1100 लाख रुपए का प्रावधान और एनडीआरएफ के तहत नल नालियों के निर्माण के लिए 20000 लाख का बजट, प्रति एमआईसी सदस्य को 01 हजार लाख अतिरिक्त विकास राशि दी जाएगी। महापौर पद के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया। मेयर ने खुद के लिए विकास कार्यों के लिए राशि का प्रावधान नहीं रखते हुए सदन और नगर निगम अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा है।

जमकर हुआ हंगामा

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सामाजिक संस्थाओं को अनुदान और एमआईसी मेंबर को राशि देने को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि 300 से ज्यादा संस्थाओं को लाखों करोड़ों क्यों ? सिर्फ बीजेपी को स्पोर्ट करने वाली संस्थाओं को अनुदान राशि दी जाती है। धार्मिक समितियों से लेकर सामाजिक संगठनों को अनुदान राशि देने का विरोध किया गया। बीजेपी पार्षदों ने आरोपों का सबूत मांगा और कहा कि विपक्ष माफी मांगे। हंगामा के चलते विपक्षी पार्षदों ने आसान को घेर लिया। वहीं परिषद में गजब नजारा भी देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद धरने पर बैठे। जिसके बाद निगम परिषद की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए की निधि देने का विरोध, कांग्रेस पार्षदों ने की नारेबाजी

भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इससे भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे। गुरुवार को महापौर मालती राय ने नगर निगम का बजट पेश किया। एमआईसी मेंबर और पार्षदों के साथ सदन में पहुंचीं महापौर सफेद-नीले कलर के झोले में बजट की कॉपी लेकर पहुंचीं। उनके साथ निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी थे। इससे पहले बैठक में निगम कमिश्नर द्वारा पार्षद को हटाने के प्रस्ताव का मुद्दा गरमा गया। पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे में महापौर मालती राय ने भी कहा कि किसी पार्षद के खिलाफ शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले एमआईसी या परिषद से चर्चा होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों के व्यवहार और फोन न उठाने की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर की गई। बीजेपी पार्षद एक स्वास्थ्य अधिकारी पर भड़क गए। पार्षद पप्पू विलास घाड़गे ने कहा कि एएचओ ने पार्षद के साथ अभद्रता की है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष बोलीं–टैक्स बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट जाएंगे

प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि धारा 132 की उप धारा में प्रावधान है कि 31 मार्च के बाद कोई कर नहीं बढ़ा सकते। फिर नगर निगम ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की हिटलरशाही है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी घेरी, कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित

एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए की निधि देने के मुद्दे पर नगर निगम की बैठक में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी पार्षदों ने निधि देने का विरोध किया तो एमआईसी मेंबर और भाजपा पार्षद संपत्ति कर के आधार पर ही वार्डों में राशि देने की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष अध्यक्ष की कुर्सी के सामने आ गए। कांग्रेसी पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी घेर ली। वही दोनों पक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई

300 से ज्यादा संस्थाओं को अनुदान देने का भी विरोध

बजट पर चर्चा के दौरान शहर की 300 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को अनुदान के रूप में लाखों रुपए दिए जाने का विरोध भी हुआ है। कांग्रेस के पार्षद मोहम्मद सरवर ने कहा कि कई संस्थाएं सक्रिय नहीं है। नगर निगम अपना पैसा सस्ता को क्यों दे रहा है।

एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए का बजट देने का विरोध

भोपाल नगर निगम के एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए का सालाना बजट देने का विपक्ष ने विरोध किया है। चार बार के पार्षद मोहम्मद सरवर ने कहा कि बजट में हमेशा महापौर, अध्यक्ष के लिए बजट का प्रावधान रहता था।लेकिन अब तो एमआईसी मेंबर को भी बजट दिया जा रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है।जैसे ही पार्षद सरवर ने विरोध जताया सभी 10 एमआईसी मेंबर विरोध में खड़े हो गए। मोहम्मद सरवर का कहना था कि एमआईसी मेंबर सिर्फ अपने वार्ड में ही राशि खर्च करते हैं, जबकि मेंबर्स का कहना था कि हम दूसरे वार्ड में भी राशि खर्च करते हैं। इस पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दोनों पक्षों को समझा कर शांत कराया

सभी विधानसभाओं में बराबरी से बंटेगा बजट : महापौर

महापौर मालती राय ने कहा कि बजट सभी विधानसभाओं में बराबरी से बंटेगा। महापौर ने कहा कि मैंने अपना बजट सदन के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि महापौर भाषण की बुकलेट में महापौर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। बाद में एमआईसी मेंबर रविंद्र यति ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने का प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष ने आसंदी ने कहा कि महापौर ने सदन पर अपनी निधि की बात छोड़ी थी।

खंडवा में गणगौर विसर्जन के लिए सफाई करने उतरे थे कुएं में

जहरीले गैस के कारण 8 की मौत

खंडवा (नप्र)। खंडवा में 8 लोग एक कुएं में डूब गए। इनमें से 7 के शव निकाल लिए गए थें। मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसडीईआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इससे पहले गांव के लोगों ने भी अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया।

घटना गुरुवार शाम को जिले के छैगांवमाखन क्षेत्र के कोंडावत गांव की है। बताया जा रहा है कि गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने ये लोग नीचे उतरे थे। कुएं में बड़ी मात्रा में गाद जमी हुई है, इसी गाद के नीचे सभी के दबे होने की आशंका है। मौके पर दो एंबुलेंस भी पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त कुछ लोग कुएं में उतरे थे, जो शाम तक बाहर नहीं निकले। कौन लोग कुएं में उतरे थे, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

एसडीईआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी– घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ही एसडीईआरएफ का 15 सदस्यीय दल भी मौके पर पहुंच गया है। एक दल रस्सी और जाली लेकर कुएं में उतरा है। फिलहाल डूबने वालों की सर्चिंग की जा रही है।

जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका– प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिस कुएं की सफाई के लिए 7 लोग नीचे उतरे थे, उस कुएं के किनारे एक नाली निकलती है, इस नाली के जरिए गांव का गंदा पानी कुएं में जाता है। जिससे कुआं दलदल में तब्दील हो गया है। इसी दलदल की सफाई के लिए ग्रामीण कुएं में उतरे थे। आशंका जताई जा रही है कि गंदगी के कारण कुएं में जहरीली गैस बन गई, जिससे इन लोगों का दम घुटने लगा था।

एमपी में 'हाई रिस्क' पर 9 हजार से ज्यादा महिलाएं, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

भोपाल (नप्र)। भोपाल जिले की 9458 गर्भवर्ती महिलाएं हाई रिस्क पर हैं। इन्हें पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। ये एनीमिया समेत अन्य तरह की दिक्कतों से ग्रसित हैं। जिले की महिला एवं बाल विकास की नियमित समीक्षा रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। अगले दो से पांच माह में इनका प्रसव भी होना है। इधर, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन महिलाओं की नियमित जांच करने को कहा है।

हाईरिस्क की वजह

आयरन और फॉलिक एसिड की कमीः इससे कमजोरी की स्थिति है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, और मिनरल्स की कमी है। अत्यधिक वजन, पानी की कमी के साथ जीवनशैली और पर्यावरणीय कारणों से को हाइरिस्क की वजह बताया जा रहा है।

बचाव के लिए इन पर फोकस

- नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है। प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर आहार देने को कहा जा रहा है।
- साफ-सफाई पर ध्यान देने के साथ दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी रही है। समय पर जरूरी टीकाकरण के निर्देश दिए हैं।
- 49 हजार 558 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ।
- 38 हजार 313 का पहला चेकअप हो चुका है।
- 9 हजार 458 महिलाएं हाईरिस्क में हैं

कुशल वित्तीय प्रबंधन से संभव हो रहा है विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जन हितैषी कार्यों का विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार सुशासन के मूल भाव को कर रही साकार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनहितैषी संकल्पों के साथ अग्रसर है। उद्योग-व्यापार से लेकर खेलों तक राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग में सुशासन के मूल भाव के साथ गतिविधियों की मॉनिटरिंग जारी है। राज्य सरकार के हर विभाग ने अपने-अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अपनी पुरानी देनदारी चुका कर, नई दृष्टि से विकास के पैमानों पर आगे बढ़ रही है।विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जन हितैषी कार्यों का विस्तार इन्हीं दृढ़संकल्पों की परिणीती है। राज्य सरकार, प्रदेशवासी और अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर एक भावना के साथ प्रगति पर अग्रसर हों, इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बावजूद इसके गत वर्ष की तुलना में बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई। कुशल वित्तीय प्रबंधन और सभी के सहयोग से सरकार हर क्षेत्र में अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी

संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10-15 वर्ष तक पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में राशि आवंटित की गई है, जिससे सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही अपने अधिकारी-कर्मचारियों की बेहतरी का ध्यान रख पा रही है। उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में प्रदेश को प्राप्त हो रही उपलब्धियों का श्रेय अधिकारी-कर्मचारियों को जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पूरे देश में मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अपनी 7-8 साल पुरानी सारी देनदारी चुकाने का कार्य किया। हमारी सरकार ने एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्रीज सहित सभी प्रकार की इकाइयों को गत एक वर्ष में लगभग 5 हजार 225 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। हमारी सरकार नवीन पहलों के माध्यम से उद्योगों के लिए निरंतर सकारात्मक वातावरण बना रही है। राज्य सरकार विकास के लिए प्रदेश से जुड़ने वाले उद्योगों से किये गये अपने सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारियों का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। जेनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृहों के कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मैट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है। ताप विद्युत गृहों में उपयोग के लिए कोयला भंडारण का अग्रिम भुगतान भी सरकार की ओर से किया जा चुका है।

पिता ने गला घोंटा, दादा ने लाश डैम में फेंकी

हरदा में बेटी मोहल्ले के लड़के से शादी की जिद पर अड़ी थी ; घरवालों को था नापसंद

खंडवा (नप्र)। नाबालिग बेटी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से बात करती थी, उसे पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। उसके पिता को ये सब नापसंद था। इसी बात को लेकर पिता ने गुस्से में आकर बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दादा ने शव को बोरे में भरकर 30 किलोमीटर दूर जाकर पानी में फेंक दिया।

दरअसल, 5 दिन पहले 30 मार्च को खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र के चारखेड़ा रेलवे ब्रिज के पास युवती का शव मिला था। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी पिता और दादा को पकड़ लिया है। हत्या की ये घटना हरदा जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली नाबालिग फोन पर एक युवक से बात करती थी। पिता ने उसे ब्लॉक करने कहा था तो मोबाइल फोड़ दिया। उसके बाद भी समझाया तो उसने बात नहीं मानी। पिता ने उसका गला दबाकर मार दिया। लड़की के दादा ने शव फेंकने में मदद की। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि हत्या के मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने हत्या के बाद उसी रात एक बजे लाश को पानी में फेंका था। 4 दिन बाद 30 मार्च को लाश पानी की सतह पर मिली। शव के साथ आरोपियों का डीएनए टेस्ट होगा। घटनास्थल हरदा जिले के छीपाबड़ थाने का हैं, इसलिए केस को संबंधित थाना पुलिस को फारवर्ड करेंगे।

सागर के एक मेडिकल कॉलेज में ऑटोक्लेव मशीन का ढक्कन प्रेशर से फटा, हादसा टला

सागर (नप्र)। सागर में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में जोरदार धमाके की आवाज आई तो सभी सकते में आ गए। दहशत और आशंका से घिरे कर्मचारी जब लैब के अंदर पहुंचे तो पता चला कि लैब के एक कमरे में रखी ऑटोक्लेव मशीन का ढक्कन प्रेशर के कारण फट गया था।

सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब में जोरदार धमाके की सूचना से हड़कंप मच गया था। हालांकि कुछ देर बाद पता चला कि यह धमाका लैब में रखी ऑटोक्लेव मशीन के कारण हुआ है। मशीन पुरानी होने के कारण प्रेशर नहीं झेल पाई और उसका ढक्कन धमाके के साथ ब्लॉस्ट हो गया था।

आए दिन विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, प्रशासनिक कार्यालय भवन में तीसरी मंजिल पर स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब में जोरदार धमाके की आवाज आई थी। आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बम फट गया हो। अचानक से धमाके की आवाज सुनकर बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारी दहशत में आ गए थे। बाद में पता चला कि लैब के एक कमरे में लगी ऑटोक्लेव मशीन में प्रेशर के कारण ब्लॉस्ट हो गया था।

माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी अनुसार लैब के अंदर सेपरेट कमरे में ऑटोक्लेव मशीन को रखा गया था। मशीन स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में प्रयोग होती है। 40 लीटर क्षमता वाली यह ऑटोक्लेव मशीन इसका प्रेशर बॉल्ब खराब था। प्रेशर बॉल्ब पहले से खराब था। यह कुकर की तरह काम करता है। इसमें मीटर लगा रहता है, जिससे ट्रेम्प्रेचर एलबीएस प्रेशर का सिस्टम खराब हो गया था। प्रेशर के कारण ढक्कन फट गया और नट–बोल्ट गोलियों की तरह दीवारों में लगे थे। इस दौरान यदि कोई कर्मचारी होता तो वह बंदूक की गोली की तरह घायल कर देता। बता दें कि यह ऑटोक्लेव मशीन लैब में प्रयोग होने वावले मीडिया को स्टरलाइज करता है, वहीं जांच के बाद यूज्ड मटेरियल और वैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी करता है।

15 साल पुरानी मशीन, मेंटेनेंस नहीं हुआ

बीएमसी से मिली जानकारी अनुसार माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो ऑटोक्लेव मशीन फटी है, वह करीब 15 साल पुरानी है। इसे 2009 में खरीदा गया था। हालांकि मशीन में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेंनटेनेंस के अभाव में इसकी यह हालत हो गई और आखिरकार उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लॉस्ट हो गया। बता दें कि बीएमसी में मशीनों का रखरखाव करने के लिए एक इंजीनियर तैनात किया गया है। हाईट्स कंपनी के इस इंजीनियर को बीएमसी करीब 60 हजार रुपए महीनो वेतन देता है, बावजूद इसके मशीनों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा।

मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ उज्जैन पुलिस का एक्शन

10 लाख के 100 साइलेंसर और हूटर पर चला बुलडोजर

उज्जैन (नप्र)। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता साफ देखी जा सकती है। ट्रैफिक सुधार के लिए यातायात पुलिस जगह-जगह पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। ऐसे में करीब 100 बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पकड़ी जिनको मॉडिफाइड करवाया गया था। इन वाहनों के जब्त करने के साथ ढाई से तीन लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इन वाहनों पर लगे मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त किया गया। इसके अलावा ऐसे चार पहिया वाहन जिन पर हूटर लगे हैं उन हूटर को भी निकाला गया है।

दरअसल, पिछले एक महीने से ट्रैफिक पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त करने की कार्रवाई कर रही थी। करीब 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। गुरुवार को एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह और दिलीप सिंह परिहार की मौजूदगी में शहर के मध्य स्थित टॉवर चोक पर साइलेंसर रख दिए गए। इन पर रोड रोलर चलाया गया। करीब 15 मिनट की इस कार्रवाई में सभी साइलेंसर पापड़ बन गए। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

100 से अधिक साइलेंसर पर चला बुलडोजर– ट्रैफिक पुलिस ने करीब 110 मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर उनको पापड़ बना दिया। इन जब्त किए गए साइलेंसरों की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं, एसपी ने बताया कि इनमें से एक विदेशी साइलेंसर भी जब्त किया गया था। जिसकी कीमत करीब 1000 डालर के आसपास की थी।

एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई– एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में माता बहनें और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। लोगों से अपील है कि वह अपने वाहनों में तेज आवाज के साइलेंसर ना लगाए।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

एडिशनल एसपी ने कहा कि चालक वाहनों की बॉडी को मॉडिफाई न कराएं। वाहनों को मूल रूप में ही रहने दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी इस प्रकार के साइलेंसर लगाने वाले और लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।